

वैदेशिक क्षेत्र

भारत के वैदेशिक क्षेत्र में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में भुगतान शेष की स्थिति में सुधार को देखते हुए स्थिरता प्राप्त हुई है। भारत का विदेशी रिजर्व 10 जनवरी 2020, को यूएस डॉलर 461.2 बिलियन तक पहुंच गई भुगतान संतुलन (बीओपी) में यह सुधार चालू खाता घाटा (सीएडी) के समिति होने के कारण वर्ष 2018-19 में 2.1 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हो गया है। चालू खाता घाटे में कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के कारण हुआ है। निर्यात वृद्धि सेवा क्षेत्र में लचीलेपन के बावजूद वैश्विक निवेश, आउट पुट में मंदी तथा अत्यधिक व्यापार तनाव के कारण बाह्य मांग में कमी होने से कमजोर बनी हुई है। सेवा आयात में वृद्धि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में बढ़ोत्तरी तथा 'मेक इन इंडिया' के कारण अपरिहार्य है। पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, औषधीय फार्मूले एवं जैविक मर्दें, स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातुएं निर्यातित वस्तुओं में शीर्ष पर बनी हुई हैं, जिनमें से औषधीय फार्मूलों एवं जैविक मर्दों के संबंध में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम, स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला कोक एवं ब्रिकेट शीर्षस्थ आयातित वस्तु-समूह में हैं और वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिकी, चीन, यूईई, सउदी अरब और हांग कांग भारत के शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं। साथ ही भुगतान संतुलन में सुधार के लिए वैदेशिक वित्तीय दशाओं में राहत, एफडीआई में प्रभावी वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों की पुनः सुदृढ़ता तथा धनप्रेषणों की बड़ी प्राप्तियों का भी योगदान है। वर्ष 2019-20 में निवल एफडीआई अन्तर प्रवाह भी उत्साहवर्धन रहे हैं जिनसे प्रथम आठ महीनों में 24.4 बिलियन अमेरिकी डालर की राशि प्राप्त हुई है, जो कि वर्ष 2018-19 की संगत अवधि की तुलना में उच्चतर है। यह वैश्विक स्तर पर उस भावना को परिलक्षित करता है कि भारत की विकास गाथा और सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों पर भरोसा बढ़ा है। सितंबर 2019 के अंत में यथास्थिति, विदेशी ऋण, जीडीपी के 20.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर बना हुआ है। वर्ष 2018-19 की तुलना में जीडीपी अनुपात की दृष्टि से भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) में भी सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 से ही काफी गिरावट देखने के बाद जून, 2019 के अंत में जीडीपी के संदर्भ में भारत की वैदेशिक देयताओं (ऋण एवं इक्विटी) में वृद्धि हुई है जिसके लिए मुख्य कारकों के रूप में एफडीआई में वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों और वैदेशिक वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) का उल्लेख किया जा सकता है।

विहंगावलोकन: भारत का 'भुगतान-संतुलन'

3.1 वर्ष 2014-19 की अवधि में 7.5 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लगभग साथ-साथ, भारत की 'भुगतान शेष' स्थिति में सुधार हुआ है। यह सुधार वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक संचित विदेशी रिजर्व के 412.9 की बिलियन अमेरिकी डालर तक

पहुंचने के कारण हुआ है जोकि वित्त वर्ष 2013-14 के अंत तक केवल 304.2 बिलियन अमेरिकी डालर था। भारत जैसी खुली व बढ़ती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के लिए 'भुगतान-संतुलन' की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कच्चे तेल और इस तरह के अन्य आदानों के लिए आवश्यक आयातों के वित्तपोषण को सुनिश्चित करता है,

विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है जो देश के करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। एक ऐसे देश के लिए जो लगभग हमेशा चालू खाता घाटे की स्थिति में रहा है, अपनी आय के स्रोत में विदेशी निवेश द्वारा उतनी प्राप्ति नहीं होती है जितनी कि विदेशों को भुगतान के माध्यम से निकल हो जाती है। बीओपी की स्थिति में लगातार सुधार होना एक ऐसी वैश्विक भावना का प्रतिबिंब है जो भारत की विकास गाथा में विश्वास को सुदृढ़ करता है। यह विश्वास देश को उस वक्त अच्छी गति प्रदान करेगा जब यह यूएस \$ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए निवेश संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु विदेशी बचतों के प्रयोग में वृद्धि करने के बारे में सोचेगा।

3.2 वर्ष 2019-20 में जीडीपी वृद्धि में काफी गिरावट के बावजूद वैश्विक भावना सकारात्मक ही रही है। भुगतान शेष/में सुधार हुआ है। मार्च-2019 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार \$ 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर-2019 में बढ़कर \$ 433.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 10 जनवरी, 2020 को \$ 461.2 बिलियन हो गया। किन्तु अभी भी इस सुधार में भेद्यता का अन्तर्भाव बना हुआ है। वर्ष 2014-2019 के विपरीत जब कच्चे तेल के मूल्य में तेज गिरावट के साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह बढ़ गया और भुगतान संतुलन में सुधार हुआ; वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में होने वाला सुधार आयात वृद्धि दर के कम होने के बाद सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में कमी तेज गिरावट के साथ हुआ है, यहां कुछ हद तक कच्चे तेल के दामों में कमी भी आयी और विदेशी

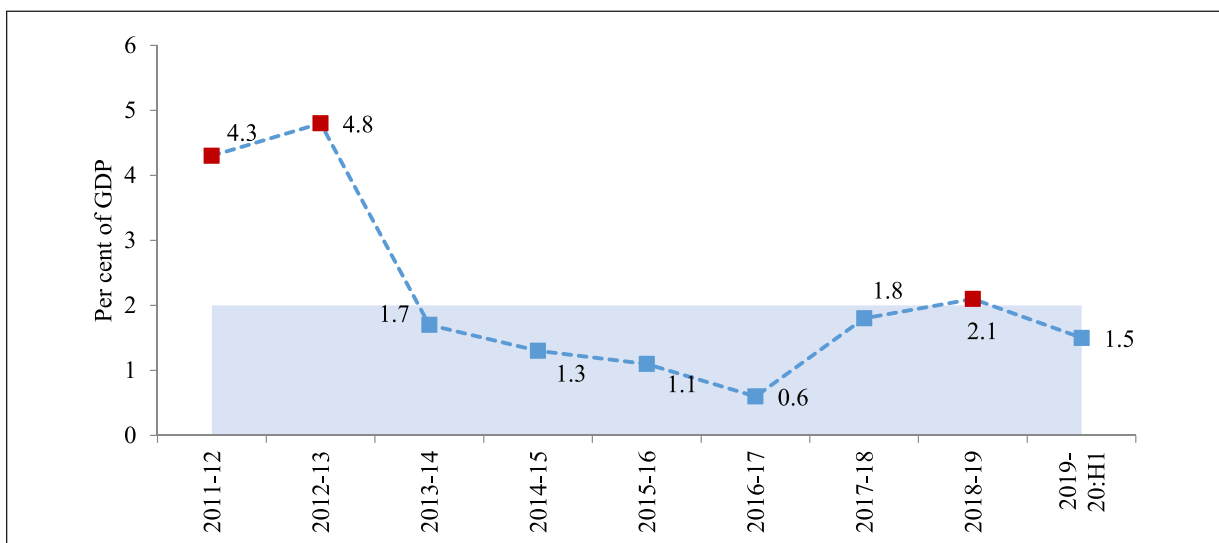
प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह सतत् रूप से उच्च स्तर पर बना रहा। देश की भुगतान-संतुलन स्थिति को सुधारने में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का कमजोर होना “शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) तथा शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (नेट एफपीआई) दोनों के लिए चुनौती देने वाला है। यदि भारत की प्रत्याशित आर्थिक वृद्धि में ऐसे निवेशों की कमी की पृष्ठभूमि बन गयी तो भुगतान शेष की स्थिति बिगड़ सकती है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में विदेशी बचत को देश में लाना कहीं अधिक कठिन हो जाएगा।

3.3 भुगतान-शेष के कुछ ऐसे घटक हैं जिनसे वर्ष 2014-19 तथा वर्ष 2019-20 दोनों ही अवधियों में भुगतान-शेष की स्थिति में सुधार हुआ है अथवा बाधाएं खड़ी हुई हैं। प्रभावी नीतियों के माध्यम से वे घटक जिनसे सुधार हुआ है उन पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा जिन घटकों से बाधाएं हुई हैं उन को पुनः क्रियाशील बनाया जाएगा। 2019-20 के आंकड़े अनंतिम हैं। वर्ष 2014-19 से 2019-20 (अप्रैल से सितंबर) तक की अवधि की भुगतान-शेष तालिका को अनुलग्नक-1 में दिखाया गया है।

क. चालू खाता घाटा (सी.ए.डी.)

3.4 चालू खाता घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वृद्धि होने से भुगतान-शेष बिगड़ जाएगा क्योंकि विदेशी-मुद्रा रिजर्व घट जाएगा अथवा ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी जिनसे विदेशी कर्ज का भार बढ़ जाएगा। तथापि यह ‘चालू खाता घाटा सकल घरेलू

चित्र 1: चालू खाता घाटा



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

उत्पाद' के अनुपात का केवल मामला नहीं है, जिसमें वर्ष 2009-14 से 2014-19 तक की अवधि में महत्त्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है (तालिका 1)। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में 'सीएडी/जीडीपी अनुपात' के कम रहते हुए भी सुधार हो रहा है (चित्र 1)।

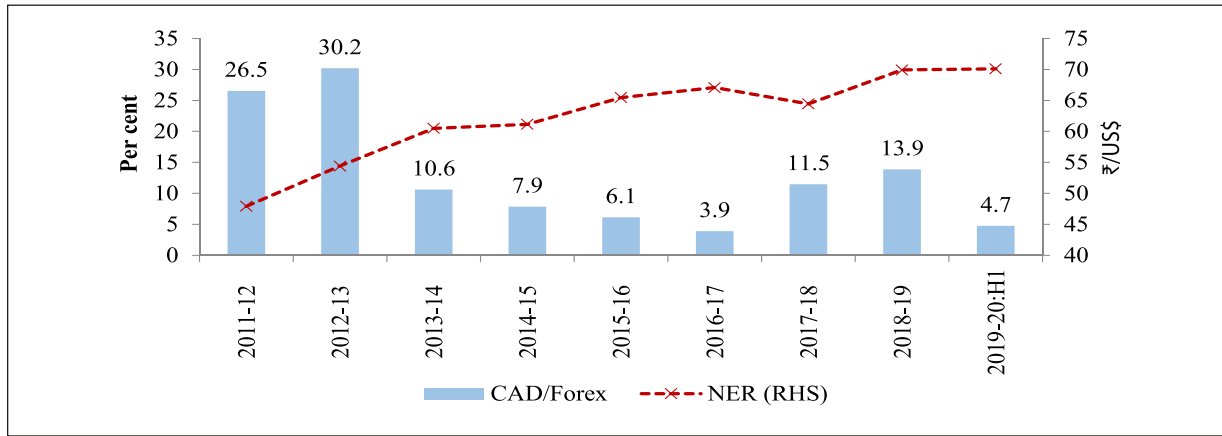
तालिका 1: चालू खाता घाटा सीएडी/जीडीपी (चालू खाता घाटा/सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
-3.3	-1.4	-2.1	-1.5

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

3.5 चालू खाता घाटे की पूर्ति विदेशी मुद्रा रिज़र्व करता है, यहां, “चालू” खाता घाटा/विदेशी मुद्रा-रिज़र्व अनुपात” के बढ़ने से कमी को पूरा करने वाली विदेशी मुद्रा का रिज़र्व घट जाता है। इस शक्ति के घटने से मुद्रा मूल्य हास होता है। यह अनुपात 2013-14 में 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 13.9 प्रतिशत हो गया, जिसके कारण भारतीय रुपये का मूल्य इन दो समय अंतरालों में एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में 69.92 रुपये से घटकर 60.50 रुपए हो गया। जैसा कि सांकेतिक विनिमय दर (एनईआर) वर्ष 2019-20 में लगभग स्थिर रही है तो इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्ति करने वाली विदेशी मुद्रा शक्ति में परिवर्तन

चित्र 2: चालू खाता घाटा/विदेशी मुद्रा और सांकेतिक विनिमय दर की प्रवृत्ति



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

नहीं हुआ है। यदि अन्य संगत कारकों में परिवर्तन नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में सांकेतिक विनिमय दर घट जाने से आयात होने वाली वस्तुएं महंगी हो जाएंगी विदेशी-निवेश-सूची में निवेशक निरुत्साहित हो जाएंगे जिसके परिणामस्वरूप भुगतान-शेष पर दबाव बढ़ जाने से यह और क्षीण हो जाएगा।

क.1. पण्य व्यापार घाटा

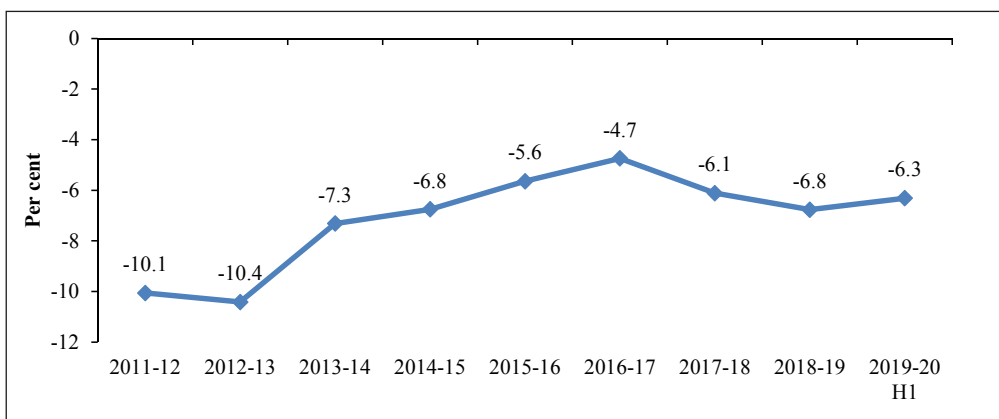
3.6 वाणिज्यिक व्यापार घाटा वैश्विक आर्थिक क्रियाकलापों में वसूली के साथ 2020 में भारत के चालू खाता घाटे के सबसे बड़े घटक हैं। तथापि वैश्विक श्रृंखला की भावी संरचना और प्रौद्योगिकी पर व्यापार तनाव के परिणामों की अनिश्चितता बढ़ गई है जो विश्व व्यापार में वृद्धि को कम कर सकती है। 2.9 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ-साथ वैश्विक

व्यापार में वृद्धि 1.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। विश्व व्यापार में मंदी अनेक कारकों के साझे प्रभाव को दर्शाता है जिनमें निवेश में गिरावट, अधिक व्यापार किए जाने वाले पूंजीगत मालों पर किए जाने वाले व्यय में कमी और कार तथा कार के पुर्जों के व्यापार में भारी गिरावट शामिल हैं। तथापि, 2020 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में सुधार होने से वैश्विक व्यापार में 3.2 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। किन्तु वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की भावी संरचना और प्रौद्योगिकी के व्यापार में कमी के अप्रत्याशित प्रभाव के संबंध में अनिश्चितता बढ़ी है जिसके कारण विश्व व्यापार में वृद्धि में गिरावट जारी रह सकती है।

3.7 औसतन, भारत के पण्य व्यापार शेष में 2009-14 की तुलना में 2014-19 सुधार हुआ है (तालिका 2),

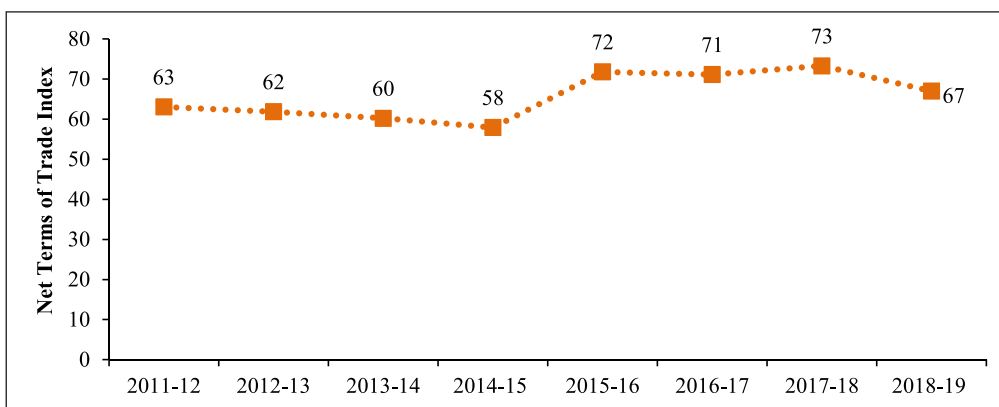
1. तथ्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से किए गए हैं।

चित्र 3: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पण्य व्यापार शेष



स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

चित्र 4: व्यापार की शर्तें (आधार वर्ष 1999-2000)



स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस), कोलकाता

तथापि बाद की अवधि में अधिकांश सुधार 2016-17 में कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक गिरावट के कारण हुआ। हाल ही में इस अनुपात में सुधार के कारण भुगतान शेष में सकारात्मक सुधार हुआ है (चित्र 3)।

तालिका 2: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पण्य व्यापार शेष

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
-8.6	-6.0	-6.8	-6.3

स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

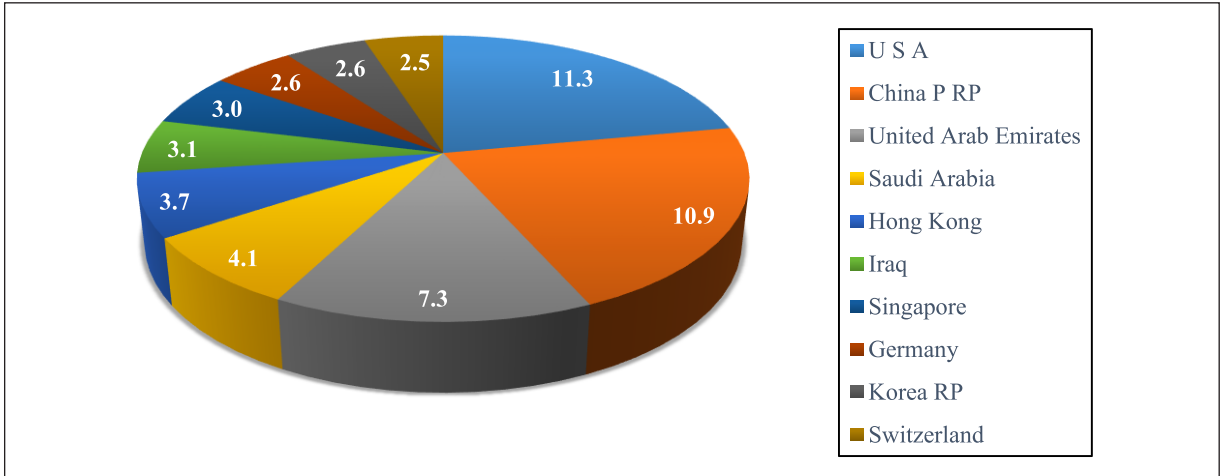
3.8 निर्यात और आयात के मूल्यों के बीच निवल व्यापार² स्थिति के प्रतिकूल होने के कारण निर्माताओं में निराशा पैदा होगी, परन्तु पण्य व्यापार घाटे में सुधार हो सकता है क्योंकि महंगे आयातों के कारण आयातित माल की खरीद कम होगी। 2017-18 से मूल्यों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव आरंभ हो गया है, जिससे भुगतान शेष के व्यापार शेष में सुधार हुआ है (चित्र 4)।

3.9 2019-20 के दौरान भारत के सबसे बड़े 10 व्यापारिक भागीदारों का भारत के कुल पण्य व्यापार में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान है (चित्र 5)³

2. निवल व्यापार शर्त ^[NTT] देश के निर्यात और आयात के इकाई मूल्यों का अनुपात है।

3. किसी व्यापार भागीदार के आयात और निर्यात का भारत के समस्त आयात और निर्यात से अनुपात उस भागीदार का हमारे पण्य व्यापार में अंश है।

चित्र 5: 2019-20 अप्रैल-नवंबर में भारत के सबसे बड़े 10 व्यापारिक भागीदार (प्रतिशत में)



स्रोत: वाणिज्य विभाग के वेबसाइट 'https://commerce-app.gov.in/eidb/default.asp' पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से परिकल्पित।

3.10 पिछले कुछ समय से सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों से संबंधित द्विपक्षीय व्यापार स्थिति नीचे तालिका 3 में दर्शायी गई है। भारत 2014-15 से लगातार दो सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार अधिशेष कर रहा है। दूसरी तरफ, भारत का अन्य बड़े व्यापारिक भागीदारों जैसे चीन

पीआरपी, सऊदी अरब, ईराक, जर्मनी, कोरिया आरपी, इण्डोनेशिया और स्विटजरलैण्ड के साथ 2014-15 से लगातार व्यापार घाटा हो रहा है। 2018-19 में भारतीय व्यापार घाटे में परिवर्तन पूर्व 2017-18 तक तो भारत का हांग-कांग और सिंगापुर से व्यापार अधिशेष था। धीरे-धीरे अधिकांश मामलों में द्विपक्षीय असंतुलन में स्थिरता आई है।

तालिका 3: द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष/घाटा (वर्ष 2018-19 से दिए गए)

(बिलियन यू.एस. डॉलर में मूल्य)

देश	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (April- November)
व्यापार अधिशेष						
संयुक्त राज्य अमेरिका	20.63	18.55	19.90	21.27	16.86	10.91
संयुक्त अरब अमीरात	6.89	10.87	9.67	6.41	0.34	0.25
व्यापार घाटा						
चीन पीआरपी	-48.48	-52.70	-51.11	-63.05	-53.57	-35.32
सऊदी अरब	-16.95	-13.94	-14.86	-16.66	-22.92	-14.32
ईराक	-13.42	-9.83	-10.60	-16.15	-20.58	-13.98
जर्मनी	-5.25	-5.00	-4.40	-4.61	-6.26	-3.09
कोरिया आरपी	-8.93	-9.52	-8.34	-11.90	-12.05	-7.80
इंडोनेशिया	-10.96	-10.31	-9.94	-12.48	-10.57	-6.99
स्वीटजरलैण्ड	-21.06	-18.32	-16.27	-17.84	-16.90	-11.97
हांग कांग	8.03	6.04	5.84	4.01	-4.99	-3.88
सिंगापुर	2.68	0.41	2.48	2.74	-4.71	-3.15

स्रोत: वाणिज्य विभाग के वेबसाइट 'https://commerce-app.gov.in/eidb/default.asp' पर उपलब्ध नवीनतम डाटा से परिकल्पित

क.1.1. पण्य निर्यात

3.11 सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में पण्य निर्यातों के अनुपात में वृद्धि का भुगतान शेष की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू अनुपात के साथ पण्य निर्यातों के अनुपात में गिरावट आई है जो भुगतान शेष की स्थिति पर ऋणात्मक प्रभाव को सूचित करता है (तालिका 4 और चित्र 6)।

तालिका 4: पण्य निर्यात/सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
15.7	12.7	12.1	11.3

स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

3.12 वैश्विक आउट पुट में मंदी जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात पर विशेष रूप से 2018-19 से 2019-20 की पहली छमाही में गिरावट का प्रभाव पड़ता है। रीअल विनमिय दन में वृद्धि (तालिका 5 चित्र -6) का भी जीडीपी अनुपात में निर्यात की गिरावट योगदान होता है।

सारणी 5: वास्तविक प्रभावी विनमिय दर (आधार 2004-05-100)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
107.1	113.9	114.0	116.5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.13 विश्व में मंदी का भारत के निर्यात पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ा है और भारत की वास्तविक विनियम दर में बढ़ोतरी वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारत के निर्यात के बढ़ते हुए एकीकरण का परिणाम है। विनिर्माण निर्यात में सापेक्षिक रूप से उच्चतर बढ़ोतरी के कारण वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण में वृद्धि हो गई है। सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पर अधिक बल देने को ध्यान में रखते हुए कुल निर्यात में विनिर्माण निर्यात के भाग में बढ़ोतरी अपरिहार्य है (तालिका 6 और चित्र 7)।

सारणी 6: कुल पण्य निर्यात में भारत में विनिर्मित पण्यों का निर्यात

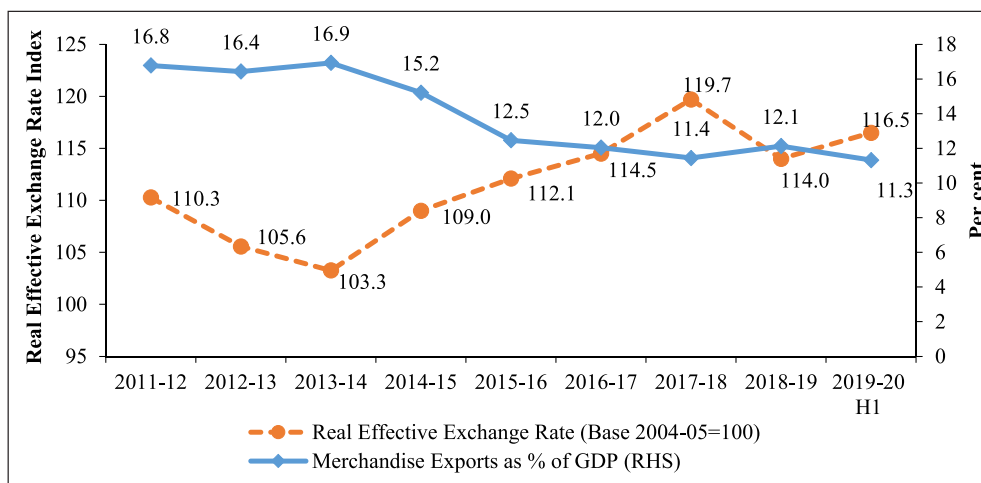
2009-13	2014-18	2017	2018
66.5	72.8	74.4	72.8

स्रोत: Trademap.org.

नोट: उल्लिखित वर्ष कैलेण्डर वर्ष है।

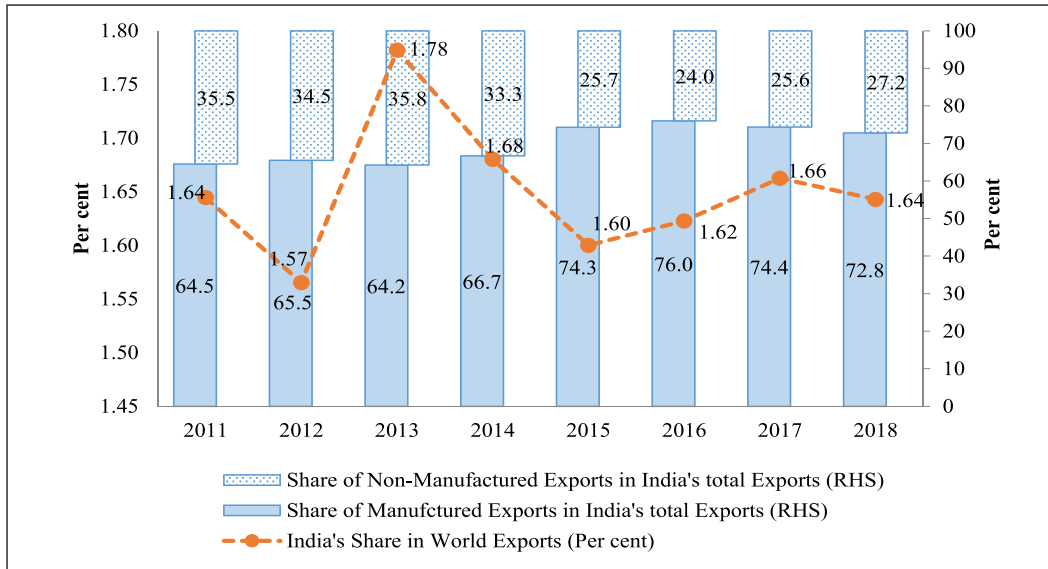
3.14 पेट्रोलियम (पीओएल) निर्यातों का भारत के निर्यात पण्यों में बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तथापि, चूंकि पेट्रोलियम निर्यात पेट्रोलियम आयातों का एक मूल्य संवर्धन मद है, अतः पीओएल निर्यातों में से शुद्ध निर्यात यह दर्शाता है कि विदेशों से होने वाले भारत के निर्यात से देश में कितना मूल्य संवर्धन प्राप्त हो रहा है। 2009-14 से 2014-19 तक गैर पीओएल निर्यातों में वृद्धि में काफी गिरावट आई है (तालिका 7 और चित्र 8)। यह एक चुनौती है जिसका आने वाले समय में समाधान करने की आवश्यकता है।

चित्र 6: वास्तविक विनमिय और जीडीपी अनुपातके रूप में पाठ्य निर्यात



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य विभाग और केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)।

चित्र 7: भारत की विश्व के निर्यातों में हिस्सेदारी, भारत के कुल पण्य निर्यातों में विनिर्मित एवं गैर-विनिर्मित मदों की हिस्सेदारी



स्रोत: Trademap.org.

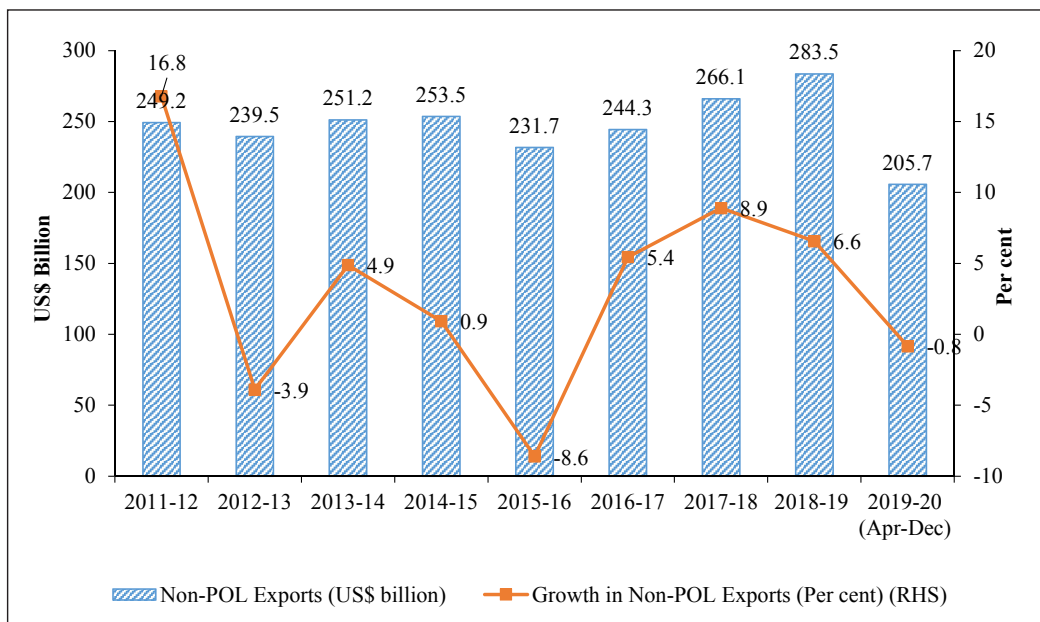
नोट: उल्लिखित वर्ष कैलेण्डर वर्ष है।

तालिका 7: गैर-पीओएल निर्यातों में वृद्धि

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 (Apr-Dec)
11.0	2.6	6.6	-0.8

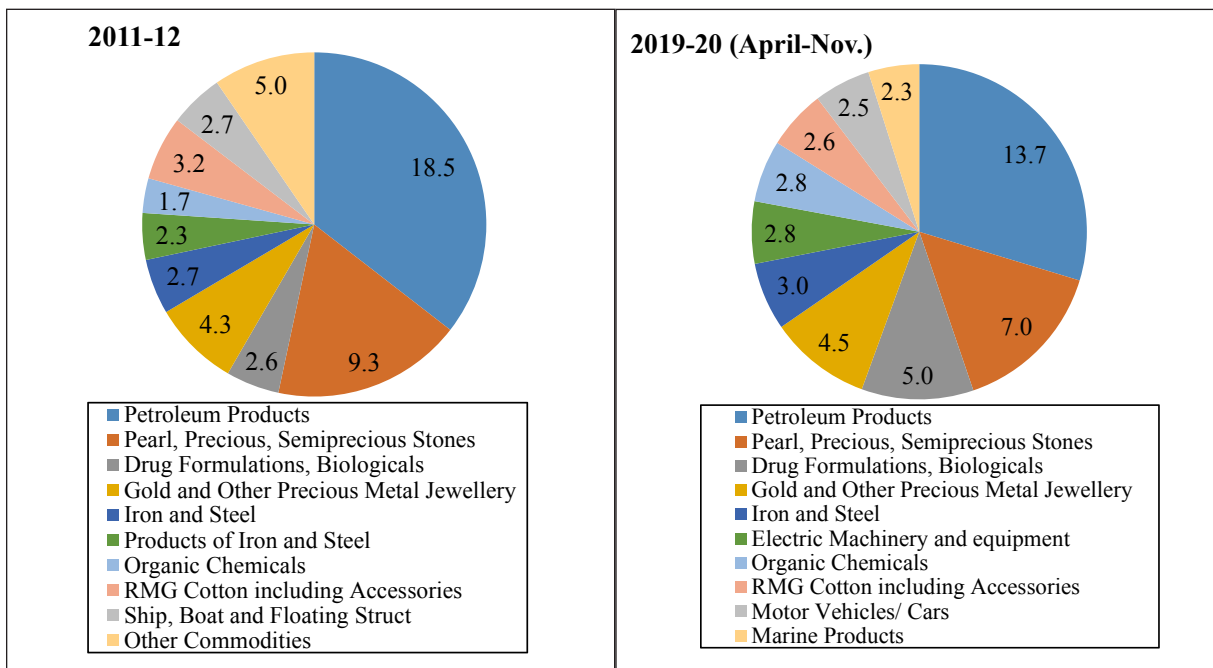
स्रोत: वाणिज्य विभाग

चित्र 8: गैर-पीओएल निर्यात एवं उसमें वृद्धि दर



स्रोत: वाणिज्य विभाग

चित्र 9: निर्यातों की पण्यवार रचना (प्रतिशत में शेयर द्वारा)

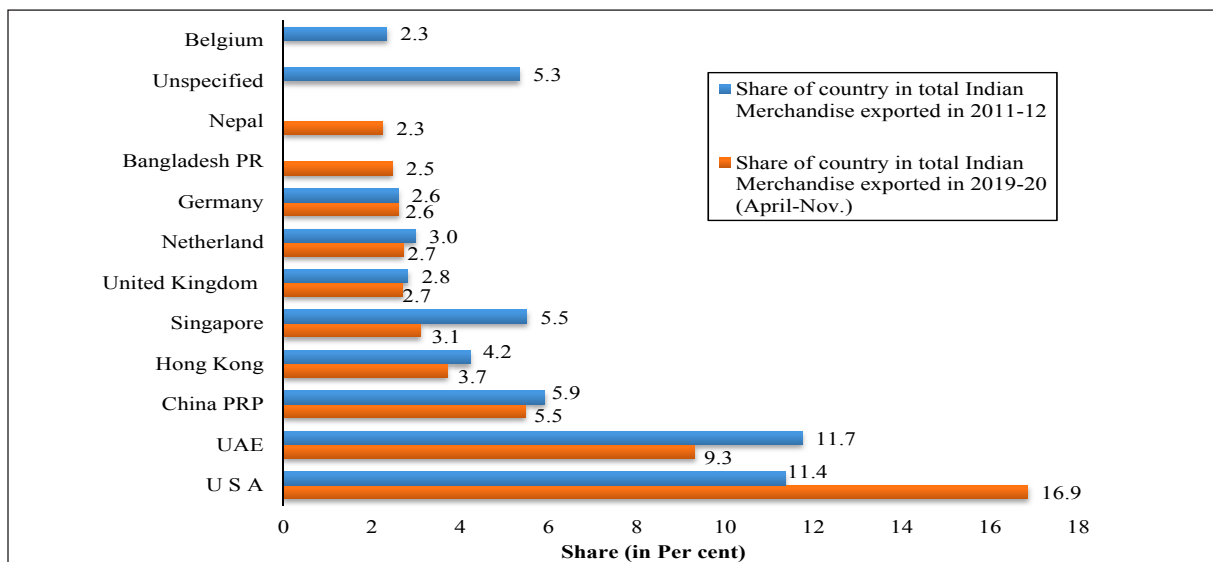


स्रोत: वाणिज्य विभाग

3.15 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में मूल्य के संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे अधिक निर्यात होना जारी रहा। वृद्धि के संदर्भ में, औषध-यौगिकों, जैवपदार्थों में 2011-12 और 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के बीच सबसे अधिक वृद्धि हुई (चित्र 9)।

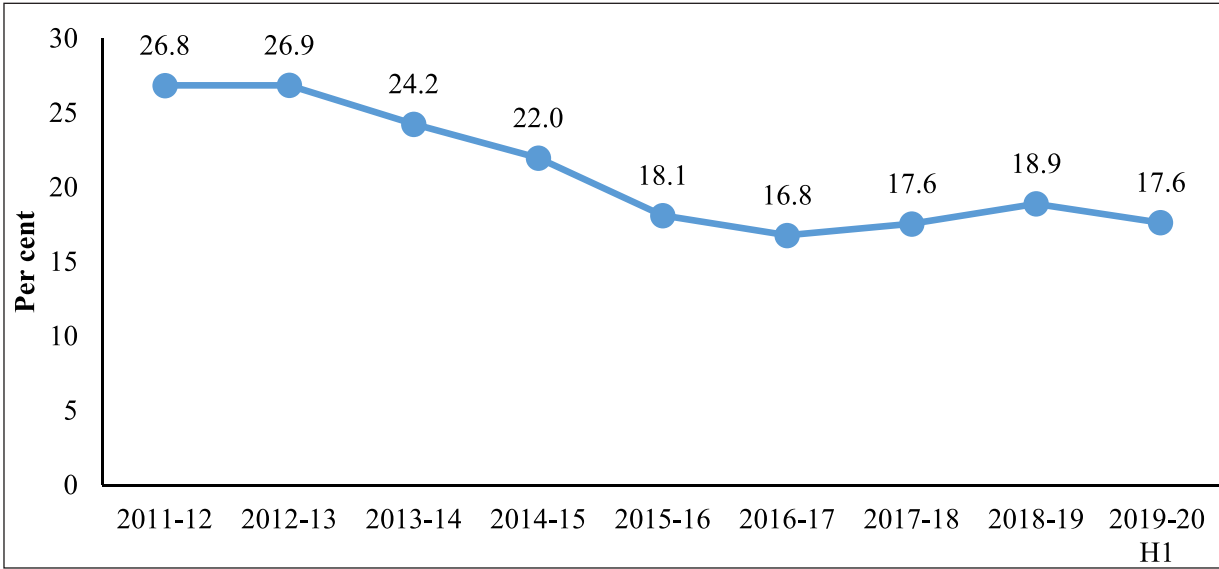
3.16 संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) भारत से सबसे अधिक निर्यात होने वाला देश रहा, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), चीन और हांग-कांग है। 2011-12 और 2019-20 के बीच यूएसए भारत से होने वाले सब से अधिक निर्यात वाला देश हो गया (चित्र 10)।

चित्र 10: 2011-12 और 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में सबसे बड़े 10 निर्यात गन्तव्य



स्रोत: वाणिज्य विभाग

चित्र 11: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत के पण्य आयात



स्रोत: वाणिज्य विभाग और केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

क.1.2 पण्य निर्यात

3.17 पण्य आयात/सकल घरेलू अनुपात में वृद्धि का भुगतान शेष की स्थिति पर निवल ऋणात्मक प्रभाव होता है। कई वर्षों से भारत में इस अनुपात में गिरावट आ रही है जो भुगतान शेष की स्थिति पर निवल सकारात्मक प्रभाव को सूचित करता है (तालिका 8 और चित्र 11)।

3.18 आयात समूह में कच्चे तेल के आयात का बहुत अधिक हिस्सा है जो कच्चे तेल की कीमतों के साथ भारत के कुल आयात तालिका से सहसंबंधित। प्रमाण भी इसकी पुष्टि करते हैं, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो कुल आयात में कच्चे तेल का अंश भी बढ़ता है जिस से सकल घरेलू उत्पाद के साथ आयात के अनुपात में वृद्धि होती है (तालिका 9 और चित्र 12)।

तालिका 8: भारत की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पण्य आयात

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20-H1
24.3	18.7	18.9	17.6

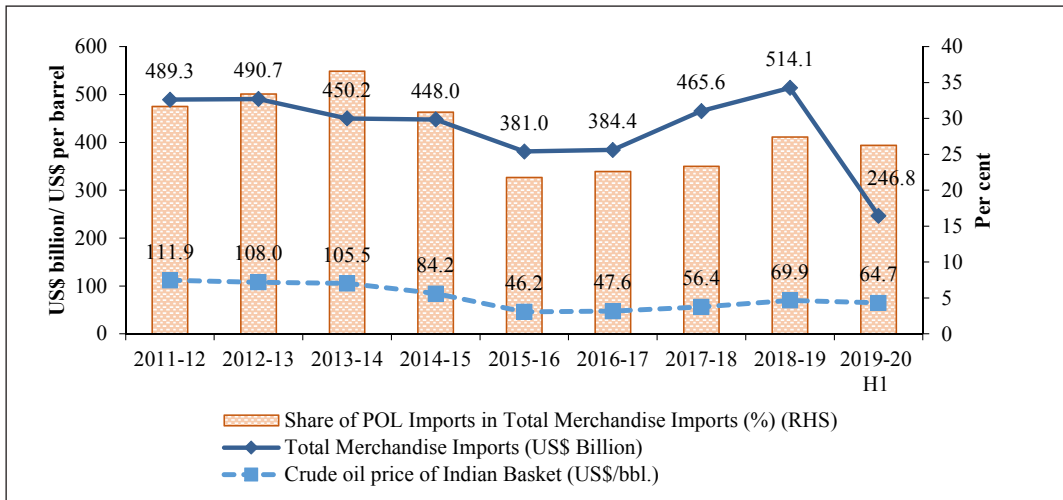
स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

तालिका 9: भारत के कुल आयात में पीओएल आयात का हिस्सा और कच्चे तेल की कीमत (भारतीय पण्य)

मद	2009-14	2014-19	2018-19	2019-20-H1
कुल आयात में पीओएल का हिस्सा (%)	32.1	25.2	27.4	26.3
भारतीय पण्य समूह में कच्चे तेल का कीमतें (बिलियन यूएस डॉलर)	96.0	60.8	69.9	64.7
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पण्य आयात	24.3	18.7	18.9	17.6

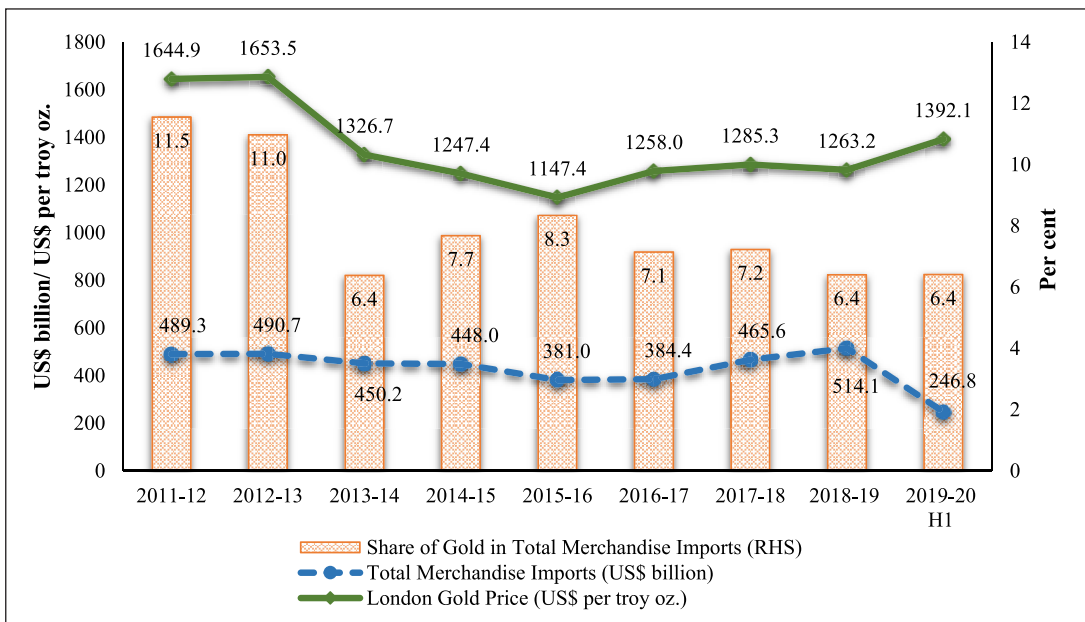
स्रोत: वाणिज्य विभाग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

चित्र 12: भारत का आयात, कुल आयात में पीओएल आयात का हिस्सा और कच्चे तेल की कीमतें



स्रोत: वाणिज्य विभाग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

चित्र 13: भारत के सोने के आयात का मूल्य एवं कीमत के संदर्भ में अंश



स्रोत: वाणिज्य विभाग एवं विश्व बैंक, पिकशीट

3.19 सोने के आयात का आयात बास्केट में महत्वपूर्ण भाग होता है जो भारत के कुल आयात का सोने की कीमतों से संबंध स्थापित करता है। जबकि व्यापक रूप में पिछली दो पंचवर्षीय अवधियों, 2009-14 एवं 2014-19, के लिए यह सच है, कि यह अंश सोने की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद 2018-19 एवं 2019-20 की पहली हमाही के बीच स्थिर रहा है, ऐसा शायद आयात शुल्क में वृद्धि होने से हुआ है जिससे सोने का आयात कम हुआ है (तालिका 10 और चित्र 13)।

3.20 हालांकि जीडीपी में पण्य आयात की गिरावट का बीओपी स्थिति पर निवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है; यह जीडीपी वृद्धि में गिरावट को भी दर्शाता है। गैर पीओएल -गैर स्वर्ण आयात निश्चित रूप से जीडीपी वृद्धि से जुड़ा है। यद्यपि दो अवधियों के बीच जब जीडीपी वृद्धि में बढ़ोत्तरी हुई तब 2009-14 से लेकर 2014-19 की जीडीपी के अनुपात में गैर पीओएल गैर तेल आयात गिरा (तालिका 11)। ऐसा खपत में वृद्धि के कारण हो सकता है, जबकि गैर पीओएल एवं गैर

तालिका 10: कुल आयातों के स्वर्ण के आयात की जिम्मेदारी और लंदन गोल्ड बिगत

कीमत	2009-14	2014-19	2018-19	2019-20-H1
कुल आयात में सोने के आयात का अंश और कीमत	10.0	7.4	6.4	6.4
London Gold Price (US\$ per troy oz.)	1388.3	1240.3	1263.2	1392.1
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक आयात	24.3	18.7	18.9	17.6

स्रोत: वाणिज्यिक एवं विश्व बैंक/पिंक स्ट्रीट विभाग

तालिका 11: गैर पीओएल, गैर स्वर्ण आयात एवं वास्तविक जीडीपी में वृद्धि

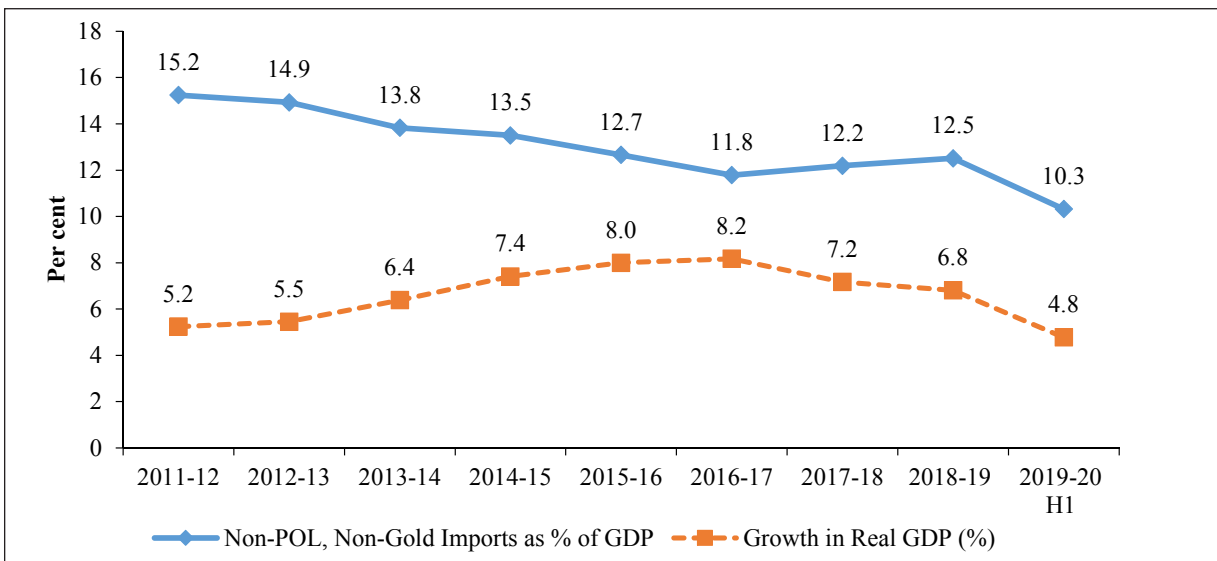
Item	2009-14	2014-19	2018-19	2019-20-H1
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर पी ओ एल, गैर स्वर्ण आयात	14.0	12.5	12.5	10.3
वास्तविक जीडीपी में वृद्धि	6.7	7.5	6.8	4.8

स्रोत: वाणिज्यिक विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

स्वर्ण आयात दर कम होने का कारण निवेश दर गिरावट है। निवेश दर में होने वाली सतत गिरावट जीडीपी वृद्धि में कमी आई है, उपभोग कम हुआ है, निवेश परिप्रेक्ष्य (आउटलुक) मंद हो गया है, जिससे आगे चलकर वर्ष 2018-19 से 2019-20 के मध्य, में जीडीपी के अनुपात के रूप में गैर-पीओएल, गैर स्वर्ण आयात के साथ जीडीपी वृद्धि में कमी आई है (चित्र 14)।

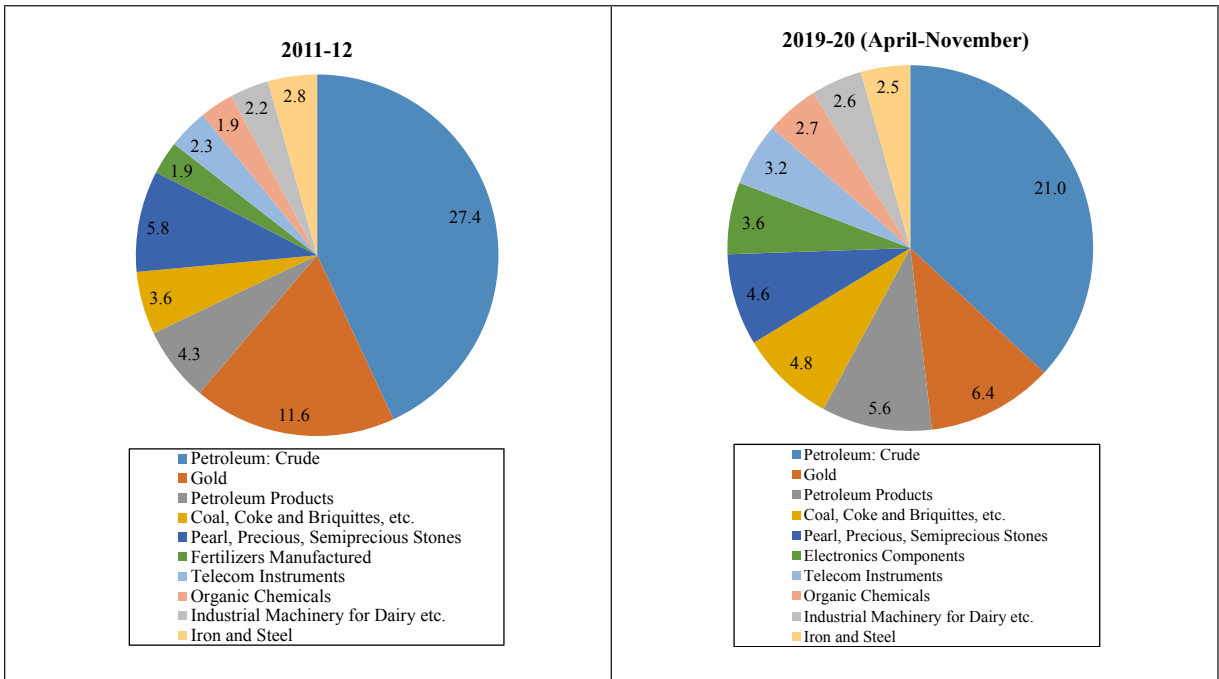
3.21 वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के आयात बास्केट में, कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा अंश था, इसके बाद सोना एवं पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं। यद्यपि वर्ष 2011-12 एवं 2019-20 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का आयात नगण्य शेष से तेजी से बढ़कर 3.6% हो गया (चित्र 15)।

चित्र 14: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर पी ओ एल, गैर गोल्ड आयात एवं वास्तविक जीडीपी में वृद्धि



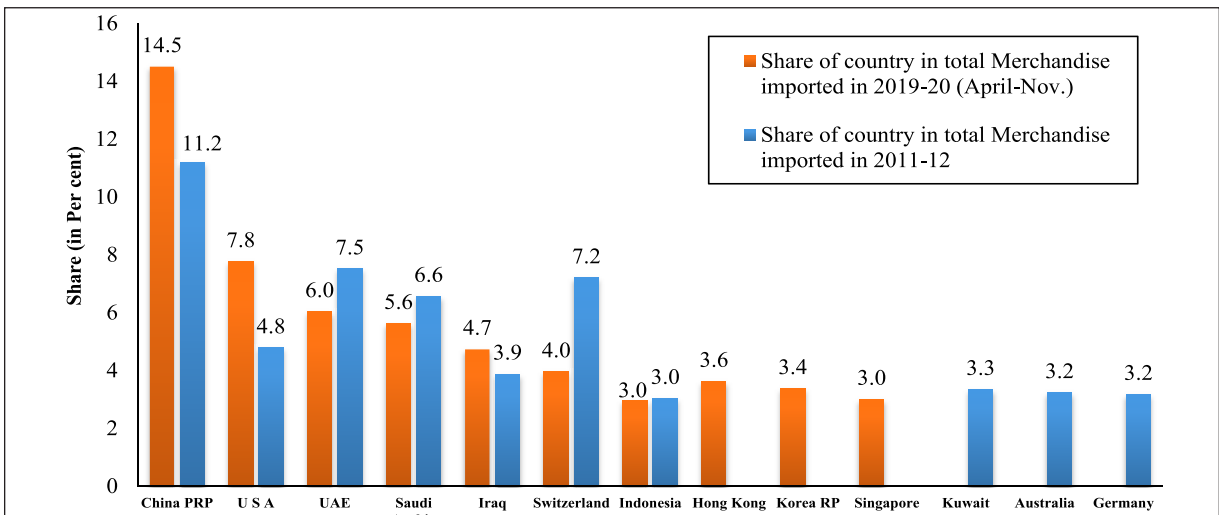
स्रोत: वाणिज्यिक विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ)

चित्र 15: आयात का वस्तुवार संगठन (% अंश अनुसार)



स्रोत: वाणिज्य विभाग

चित्र 16: 2011-12 एवं 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में भारत के 10 शीर्ष आयात उद्गम (% में शेयर द्वारा)



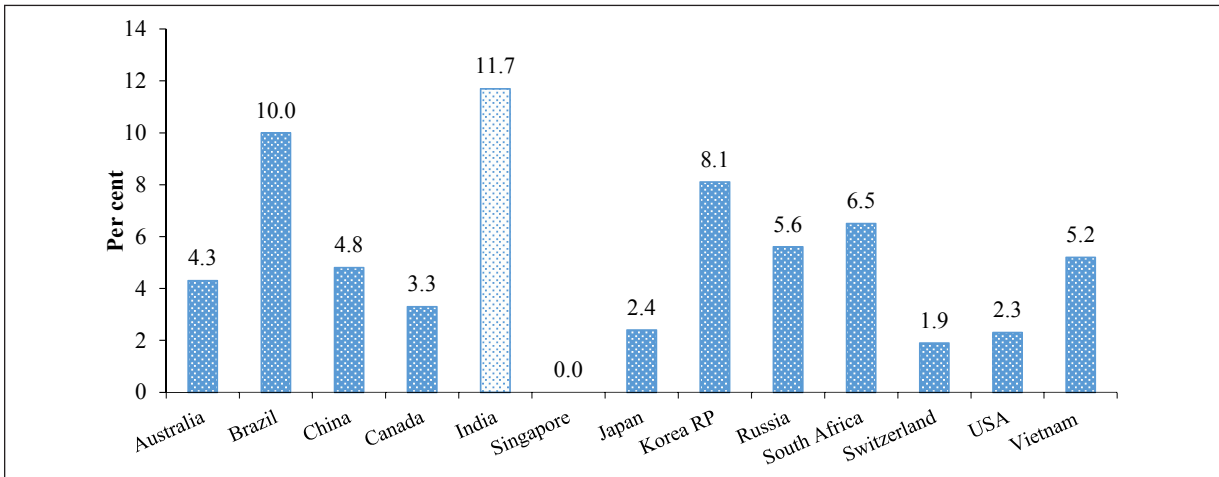
स्रोत: वाणिज्य विभाग

3.22 चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है, इसके बाद सं.रा. अमरीका, यूएई एवं सउदी अरब आते हैं। हाल ही में हांगकांग, कोरिया एवं सिंगापुर भी भारत के लिए महत्वपूर्ण आयात स्रोत के रूप में उभरे हैं (चित्र 16)।

3.23 ऊंचे सीमा शुल्क के कारण, जीडीपी में वृद्धि की गति का गैर-पीओ एल-गैर स्वर्ण आयात पर पड़ने वाला प्रभाव कुछ हद तक शिथिल हो गया है, जो भुगतान-

संतुलन के खराब प्रदर्शन पर रोक लगाता है। दूसरी ओर, जीडीपी वृद्धि में कमी आती है, तो उच्च सीमा शुल्क गैर पीओएल -गैर स्वर्ण आयात के कम होने के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, जिससे बीओपी में अधिक अनुपातिक सुधार होता है। इस संबंध में भारत को अन्य देशों से अधिक सीमा शुल्क होने का लाभ हुआ है (चित्र 17) ।

चित्र 17: वर्ष 2017 के दौरान व्यापार भारित आयात सीमा शुल्क (कुल)



स्रोत: डब्ल्यू टी ओ टैरिफ प्रोफाइल डेटाबेस, 'https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tariff_profiles_list_e.htm'

क. 2. निवल सेवाएँ

3.24 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर निवल सेवाएँ बीओपी पर सेवा निर्यात और आयात के निवल प्रभाव को दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में भारत की निवल सेवां अधिशेष में धीरे-धीरे ह्रास हो रहा है। (तालिका 12 और चित्र 18)

तालिका 12: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवल सेवाएँ

Net Services/GDP			
2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
3.3	3.2	3.1	2.9

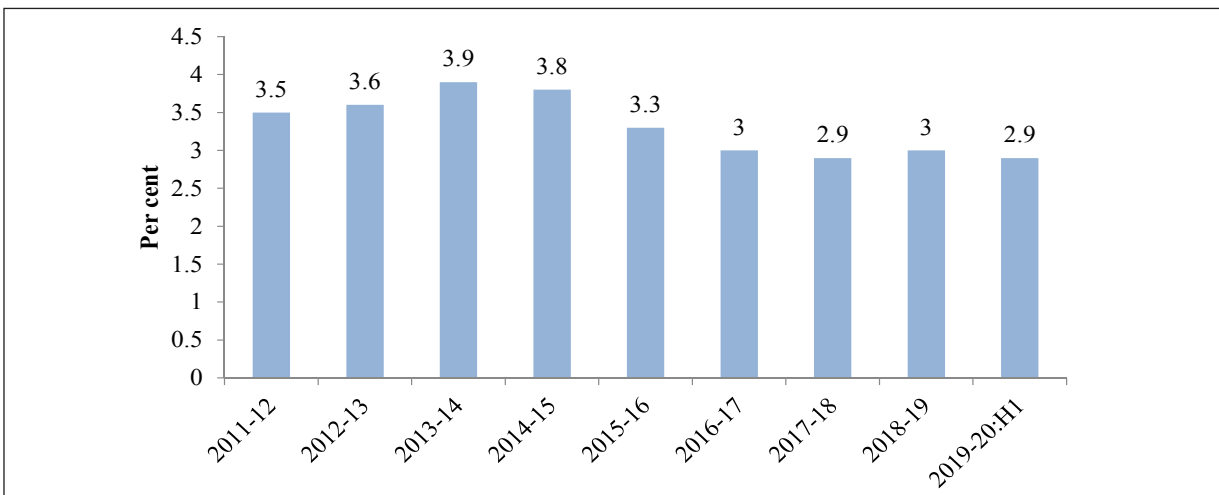
स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

3.25 निवल सेवाओं से अधिशेष व्यापार घाटे का महत्वपूर्ण रूप में वित्तपोषण कर रहा है। विगत कुछ वर्षों में आधे से कम रह जाने से पूर्व 2016-17 में व्यापार घाटे के लगभग दो-तिहाई तक वित्तपोषण इससे हो रहा था (चित्र 19)। सकल घरेलू उत्पाद में निवल सेवाओं की धीमी गिरावट होने से वित्तपोषण उस समय तक धीरे-धीरे गिरता जाएगा जब तक कि जीडीपी के संबंध में पण्य वस्तु घाटे में सुधार न आ जाए।

क. 2.1 सेवा निर्यात

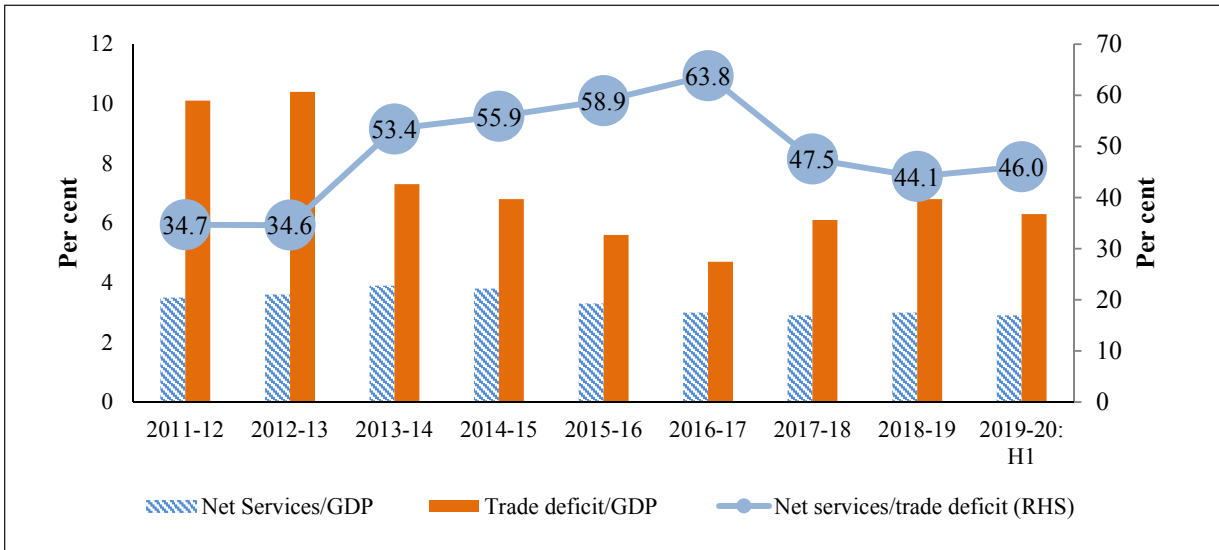
3.26 सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में होने वाली सेवा निर्यात वृद्धि का बीओपी परिवेश पर निवल सकारात्मक

चित्र 18: निवल सेवा जीडीपी अनुपात के रूप में



स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

चित्र 19: निवल सेवाएं और व्यापार घाटा



स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

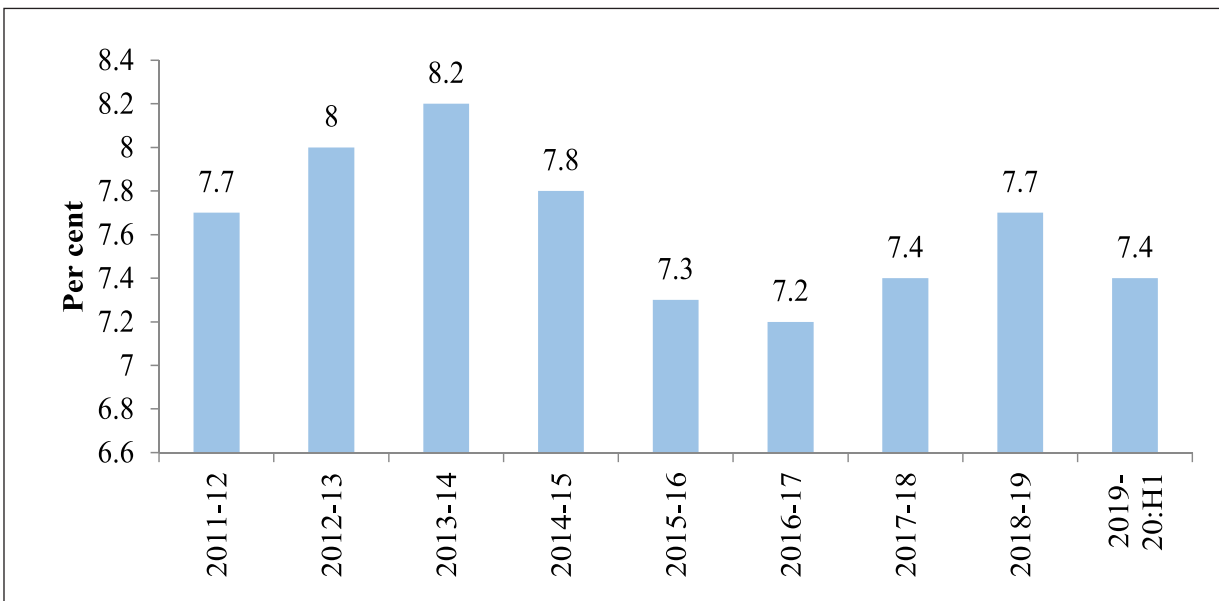
प्रभाव होता है। भारतीय सेवा निर्यात सत्त रूप से जीडीपी के 7.4 से 7.7 प्रतिशत के बीच रहा जो बीओपी के स्थायित्व में योगदान करने वाले इस स्रोत की निरंतरता को प्रदर्शित करता है (तालिका 13 और चित्र 20)।

तालिका 13: जीडीपी के अनुपात के रूप में सेवा आयात

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
7.7	7.5	7.7	7.4

स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

चित्र 20: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा निर्यात

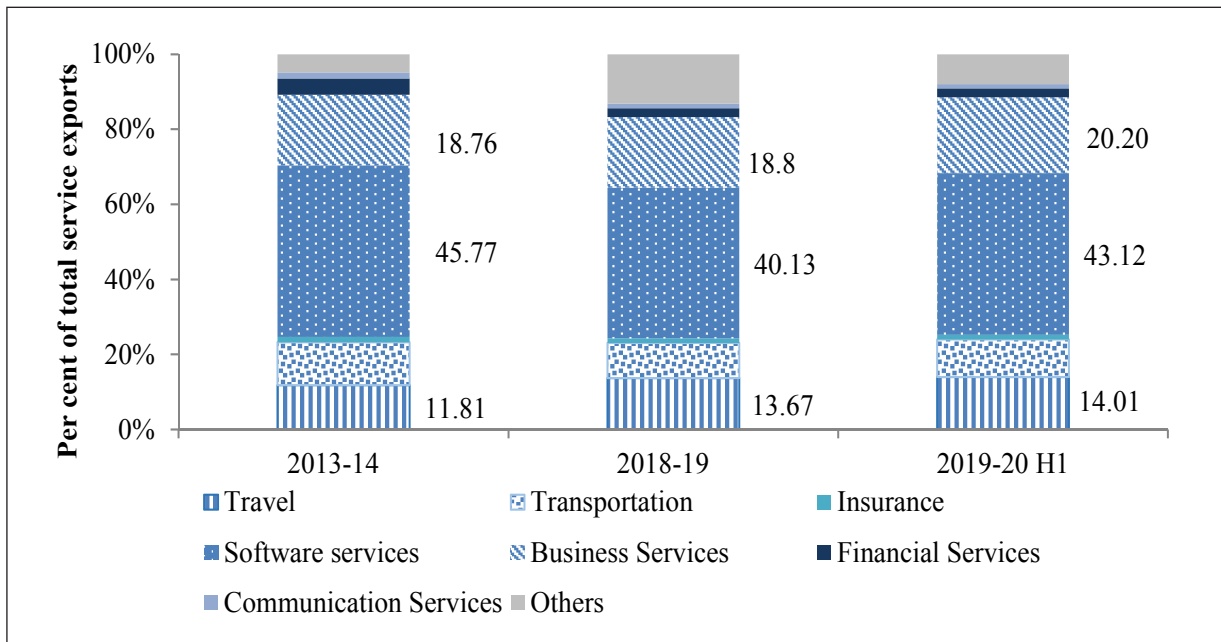


स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

3.27 वर्षों से सेवा निर्यात की रचना काफी हद तक अपरिवर्तित रही है। इसमें सॉफ्टवेयर सेवाओं का योगदान बहुत ज्यादा है, लगभग 40 से 45 प्रतिशत है, इसके

बाद व्यापार सेवाएं आती हैं जिनकी भागीदारी 18 से 20 प्रतिशत है, पर्यटन की भागीदारी 11-13 प्रतिशत एवं परिवहन की भागीदारी 9 से 11 प्रतिशत है (चित्र 21)।

चित्र 21: सेवा निर्यात संरचना



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

क. 2.2 सेवा आयात

3.28 जीडीपी अनुपात में सेवा आयात में वृद्धि का बीओपी स्थिति पर निवल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में, जीडीपी के संबंध में सेवा आयात में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे बीओपी पर दबाव बढ़ रहा है (तालिका 14 चित्र 22)। हालांकि, एफडीआई में वृद्धि एवं 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में उत्तरोत्तर प्रगति से

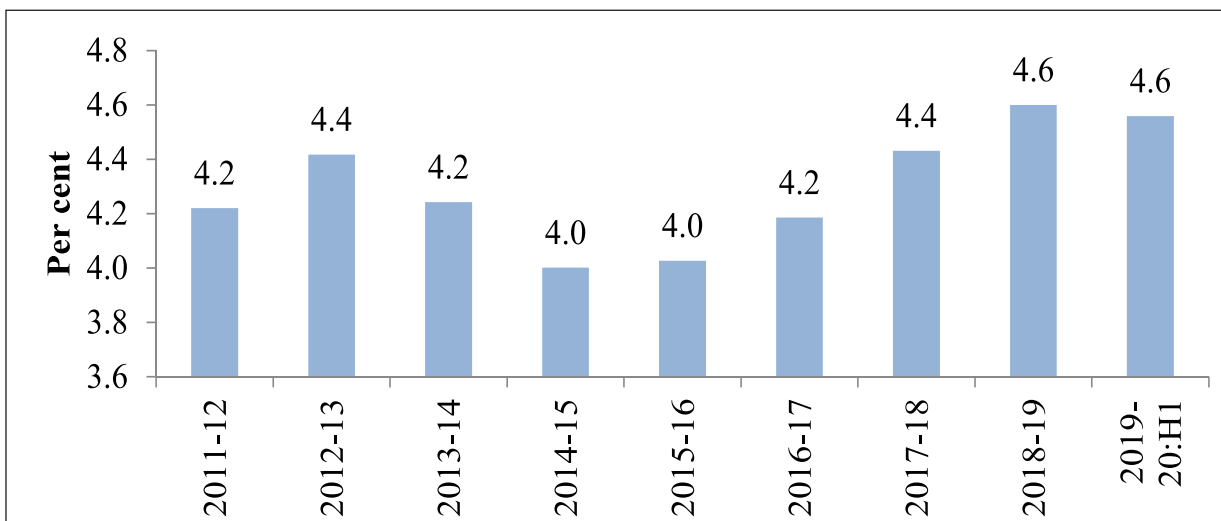
जीडीपी अनुपात में सेवा के आयात में वृद्धि होना अवश्यभावी है।

तालिका 14: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा आयात

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
4.4	4.3	4.6	4.6

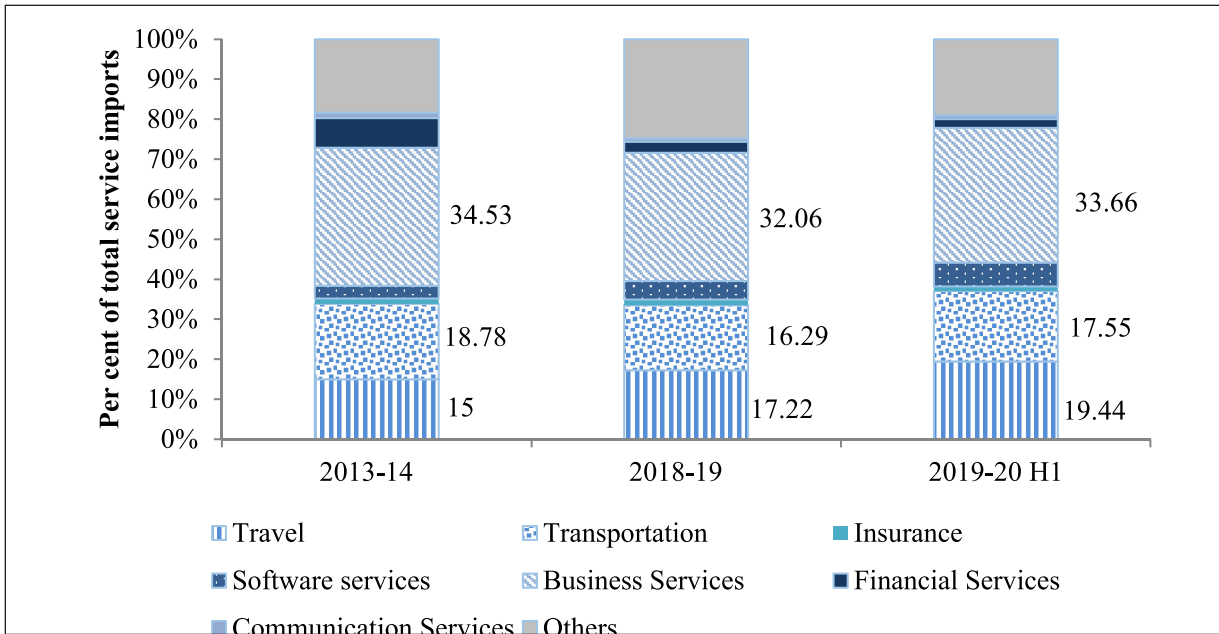
स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

चित्र 22: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा आयात



स्रोत: भारत रिजर्व बैंक

चित्र 23: सेवा आयात संरचना



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.29 सेवा आयातों के विभिन्न घटकों के सापेक्षिक हिस्से और व्यवसायिक सेवा, जो कि सेवा आयात का लगभग एक तिहाई है, के साथ अधिक बदले नहीं है, यह देश में आर्थिक गतिविधि के बढ़ते स्तर के अनुरूप है। हालांकि, पर्यटन सेवा के घटक में लगातार वृद्धि हो रही है, जो उच्च मध्य वर्गों में वैश्विक गंतव्यों के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है (चित्र 33)।

क. 3 नीति पर्यावरण

क. 3.1 भारत और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

3.30 भारत ने 13-14 मई, 2019 को नई दिल्ली में व्यापार मंत्रियों के साथ मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की जिसमें सदस्य देशों के लिए, जो चिंता का विषय है, उस पर विचार-विमर्श करने के लिए महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन के साथ सोलह विकासशील और छह सबसे कम विकसित देशों ने भाग लिया। बैठक का समापन एक परिणाम दस्तावेज के साथ हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को तय किया गया और विश्व व्यापार संघ की विवाद निपटान प्रणाली द्वारा सामना किए जाने वाले चुनौतियों का समाधान करने की परिकल्पना की गई है।

3.31 भारत भी अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल की बैठक में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है, जिन पर विश्व व्यापार संगठन में सुधार करते समय ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यह अपेक्षा की गई है कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मुख्य सिद्धांतों के संरक्षण, विशेष और विभेदक उपचार के प्रावधानों की रक्षा, अपीलीय निकाय संकट के समाधान, एकतरफा कार्रवाइयों का निपटान किया जाए और अधिदृष्ट क्षेत्रों में विचारविमर्श जारी रखा जाए। विशेष रूप से भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में विकासशील देशों के बेहतर एकीकरण के लिए विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान आवश्यक हैं। ये प्रावधान विश्व व्यापार संगठन के मूल में हैं और इनको अवश्य संरक्षित किया जाना चाहिए।

3.32 इसके अलावा, भारत और क्यूबा सहित अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा विश्व व्यापार संगठन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अधिसूचना की आवश्यकता के बात पर जोर दिया गया है। इस प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा बताती है कि विश्व व्यापार

संगठन के सभी कार्यों में पारदर्शिता एक सामान्य सूत्र होना चाहिए। कम विकसित देशों सहित विकासशील देश, जो पहले से ही संसाधन/क्षमता से बाधित हैं, को पारदर्शिता में सुधार के नाम पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

3.33 विश्व बैंक संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2020 में नूर-सुल्तान कजाकिस्तान में आयोजित किया जाना है। विश्व बैंक की विभिन्न अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठकों और नियमित बैठकों में एमसी 12 के परिणामों पर चर्चा चल रही है। विचार विमर्श के विभिन्न क्षेत्रों में धारित पदों के संबंध में सदस्यों में भारी मतभेद होने के बावजूद भारत नियमित रूप से सदस्यों से ऐसे समाधान तलाशने के लिए बातचीत कर रहा है जिससे कि विश्व बैंक संगठन की बहुत से सदस्यों की समस्याओं का समाधान होता है।

3.34 भारत समय-समय पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक भण्डारधारण में एक स्थायी समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालांकि, बातचीत के इस क्षेत्र में रचनात्मक कार्य नहीं हुआ है। इसके अलावा भारत विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य सब्सिडी वार्ता में पूरी तरह से जुड़ा है और गरीब छोटे और कारीगर किसान के हितों की रक्षा को प्राथकिमता के रूप में मानता है।

3.35 भारत की बहुत से क्षेत्रीय समूहों/देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्थाएं हैं। मुक्त व्यापार करार (एफटीए) और अधिमानी व्यापार समझौता (पीटीए) पहले से लागू हैं और चालू व्यापार पर वार्ताओं की सूची परिशिष्ट II में दी गई है।

3.2 व्यापार सुगमता

3.36 भारत ने अप्रैल, 2016 में व्यापार सुगमता संबंधी विश्व बैंक संगठन करार की अभिपुष्टि की थी और तदनुसार इसका कार्यान्वयन आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति (एनसीटीएफ) गठित की थी। व्यापार सुगमता के लाभ का अनुकूलन करने के लिए, जिससे कि व्यापार की वर्तमान बुनियादी ढांचे की बाधाओं को अधिक सुगम बनाया जा सके, राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना (एनटीएफपी 2017-20)

विशिष्ट गतिविधियों सहित तैयार की गई थी जिसे भारत की व्यापार की सक्रिय सुगमता प्रदाता छवि के लिए सरकार का समग्र दृष्टि कोण दर्शाने के लिए 20 जुलाई 2017 के जारी किया गया था। तब से एसीटीएफ ने निर्यात और आयात की उच्च कीमत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे देश के सीमा पर व्यापार को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से एकीकृत किया जा सके। सतत व्यापार सुगमता व्यापार के परिणाम स्वरूप भारत ने 'सीमा पर व्यापार' संकेतक के तहत 2016 में 143वें स्थान से 2019 में 68वें स्थान पर अपनी रैंकिंग में सुधार किया जिसकी विश्व बैंक संगठन द्वारा अपनी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में लगभग 190 देशों की समग्र रैंकिंग का निर्धारण करने के लिए संवीक्षा की जा रही है।

3.37 सूचक के उप प्राचल, "सीमा पर व्यापार" के लिए नामित, दस्तावेज अपेक्षाओं के साथ समय और लागत का अनुपालन करना होगा और भारत ने जब से विश्व बैंक संगठन, 2016, के व्यापार सुगमता करार को अभिपुष्टि किया है तब से निर्यात और आयात के लिए सीमा संबंधी अपेक्षाओं में महत्वपूर्ण सुधार परिलक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त कार्गो निकासी समय लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत समुद्र पत्तन, अंतरदेशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), वायु कार्गो काम्प्लेक्स और एकीकृत जांच पोस्ट को कवर करते हुए बहुत से स्थलों पर 2019 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर टाइम रिलीज स्टडी (टी आर एस) कर रहा है। राष्ट्रीय टी आर एस का अभीष्ट उद्देश्य निकासी समय को कम करने, विद्यमान प्रक्रियाओं की जांच करने, प्रौद्योगिकी और इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रशासनिक सरकारों के लिए वर्तमान उपायों के प्रभावों का मूल्यांकन करना है और जिसके द्वारा मैनुअल प्रक्रिया तथा प्रत्यक्ष स्पर्श बिंदु, मौजूदा बुनियादी ढांचे की बाधाओं को कम करने तथा समग्र रिलीज समय को कम करने में अक्षमता (पणधारकों द्वारा) की पहचान करना है।

3.38 कार्गो के निर्गमन के समग्र समय में कमी और उसके परिणामस्वरूप 'सीमापर व्यापार' संकेतक के अंतर्गत भारत की रैंकिंग में सुधार में निम्नलिखित नीतिगत पहलों का विशेष योगदान रहा है:-

बाक्स 1 मुख्य निर्यात संवर्धन योजनाएं

भारत से वाणिज्यिक वस्तु निर्यात स्कीम (एम ई आई एस): 01.04.2015 से आरंभ एम ई आई एस का उद्देश्य है भारत में उत्पादिक/विनिर्मित माल/उत्पादों के निर्यात में आने वाली अवसंरचनात्मक अदक्षताओं को दूर करना और संबंध लागतों को कम करना है। यह स्कीम निर्यातकों को किए गए निर्यात के पोतपर्यात (एफओबी) मूल के 2,3,4,5,7 प्रतिशत दर पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप से प्रोत्साहित करती है। यह स्क्रिप हस्तांतरणीय होती हैं तथा सीमा-शुल्क सहित कुछ केन्द्रीय शुल्कों/करों को अदा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। यह स्कीम 8000 से अधिक टैरिफ लाइनों के निर्यात को कवर करती है। आवेदन करने से लेकर अंतिम रूप में जारी करने की एमईआईएस स्क्रिप की प्रक्रिया शुरू से अंत तक डिजीटाइज्ड है, एच एस कूट के 99 प्रतिशत से अधिक जिन पर एम ई आई एस लागू होती है बिना किसी वैयक्तिक अंतरक्रिया के हैं।

भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम (एस ई आई एस): इस स्कीम के तहत, उन सेवा प्रदाताओं को जो भारत से शेष विश्व में अधिसूचित सेवाएं उपलब्ध करवा कर निवल विदेशी मुद्रा आय करते हैं, उन्हें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में पारितोषिक उपलब्ध है। यह स्क्रिप, एम ई आई एस की तरह ही हस्तांतरणीय है और इनका उपयोग सीमा शुल्क सहित कुछ केन्द्रीय शुल्कों/करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। सेवा निर्यातक किसी वित्त वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के निवल विदेशी मुद्रा आय (एन एफ ई ई) के 5 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की दर पर एस ई आई एस के लिए अर्ह है।

पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन (ई.पी.सी.जी.) स्कीम: यह स्कीम निर्यातकों को उत्पादन-पूर्व, उत्पादन और उत्पादन पश्चात के लिए शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात (इस स्कीम के तहत कुछ विशिष्ट मदों के अलावा) की अनुमति देती है। इसकी एवज में निर्यातक से यह अपेक्षित है कि वह स्वीकृति देने की तारीख क छह साल के भीतर, पूंजीगत माल पर बचाए गए आयात शुल्कों, करों और उप-करों से छह गुना अधिक निर्यात दायित्व पूर्ण करे। ईपीसीजी स्वीकृति के तहत, आयातित पूंजीगत माल, जो भौतिक निर्यात के लिए है को वर्तमान में 31.03.2020 तक स्वीकृति माल और सेवाएं कर (आई जी एस टी) और क्षतिपूर्ति उपकर की भी छूट प्राप्त है।

अग्रिम स्वीकृति स्कीम: अग्रिम स्वीकृति (एए) के तहत आगत के शुल्क रहित आयात की अनुमति प्रदान की जाती है जो भौतिक रूप से निर्यात उत्पादों (बर्बादी के लिए सामान्य अनुमति देना) में समाहित होती है। इसके साथ-साथ, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पादों के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त/उपयोज्य किए जाते हैं, उनकी भी अनुमति है।

सीमा शुल्क मुक्त आयात स्वीकृति (डी एफ आई ए): सीमा शुल्क मुक्त आयात स्वीकृति (डी एफ आई ए) उन उत्पादों के लिए निर्यात-पश्चात् आधार में जारी की जाती है जिसके लिए मानक आगत-निर्गत मानक (एस आई ओ एन) अधिसूचित किए जाते हैं इस स्कीम का एक उद्देश्य एक बार निर्यात होने के बाद एस आई ओ एन के अनुसार आयातित आगत अथवा स्वीकृति स्कीम के प्रावधान अग्रिम स्वीकृति स्कीम के ही समान हैं।

ब्याज समकारी स्कीम (आई ई एम): यह स्कीम 01.04.2015 के 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी हुई थी। यह स्कीम डी जी एफ टी द्वारा पूर्व और पश्च पोतलदान रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से कार्यानिवत की जाती है। इस स्कीम के तहत, अर्ह निर्यातकों को @ 3 प्रतिशत की दर से ब्याज समकर किया जाता है। 02.11.2018 से ब्याज समकारी दर, पूर्व और पश्च पोतलदान रुपया निर्यात क्रेडिट पर चालू ब्याज समकारी स्कीम (आई ई एस) के तहत एम एस एम ई क्षेत्र के निर्यात के लिए 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। 02.01.2019 से इस स्कीम के तहत ब्यापार निर्यातकों को भी 3 प्रतिशत की ब्याज समकारी दर में शामिल कर लिया गया है।

निर्यात उन्मुखी इकाइयां (ईओयू)/इलैक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईचवटीपी)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) योजना: निर्यात उन्मुखी इकाइयां (ईओयू)/इलैक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईचवटीपी)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) नामक इन चार योजनाओं का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा के अर्जन को बढ़ावा देना, निर्यात के उत्पादन के लिए निवेश को आकर्षित करना और रोजगार उत्पन्न करना है। अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं (डीटीपी के अंतर्गत अनुमत बिक्री को छोड़कर) के पूरे उत्पादन का निर्यात करने वाले उपक्रमों को इस योजना के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है। इन योजनाओं के अंतर्गत व्यापारिक इकाइयों को शामिल नहीं किया जाता। इस योजना के अंतर्गत ईओयू आदि को डीटीए या डीटीए के अंतर्गत परिबद्ध अथवा दिनांक 31.03.2020 तक भारत में आयोजित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी (जैसा कि जीएसटी परिषद तथा उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं द्वारा प्रावधान किया गया है) से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना आयात और/या खरीद की अनुमति होती है और यदि धारा 3(1), 3(3) एवं 3(5) के अंतर्गत वसूल किए जाने वाले सीमा शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क, यदि कोई हो तो और समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3(7) एवं 3(9) के अंतर्गत वसूल किए जाने वाले एकीकृत कर और जीएसटी प्रतिपूरक प्रतिकर का भुगतान किए बिना खरीद की जा सकती है।

मानित निर्यात योजना: मानित निर्यात में उन लेनदेन का संदर्भ होता है जिसमें आपूर्ति वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती और इस प्रकार की आपूर्ति का भुगतान भारतीय रुपयों में या निशुल्क विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। मानित निर्यात की योजना के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुओं और मानित निर्यात की विनिर्दिष्ट श्रेणियों को आपूर्ति वस्तुओं पर विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंतर्गत शुल्क से छूट/वापसी का प्रावधान होता है जिससे कि स्वदेशी विनिर्माताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। इस योजना में लाभों के अंतर्गत शुल्क से छूट, अंतिम बिन्दु पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की वापसी, मानित निर्यात की विनिर्दिष्ट श्रेणियों में वस्तुओं के विनिर्माण और आपूर्ति में प्रयुक्त सामग्री के कारण व्यर्थ हो गए शुल्क की वापसी शामिल होते हैं। जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शुल्क की वापसी मूल सीमाशुल्क में छूट/वापसी तक सीमित होती है।

विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए): माल के वाहनांतरण के कारण और विनिर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि के ब्रांड की पहचान को बढ़ावा देने के लिए विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात की उच्च परिवहन लागत की हानि को कम करने के लिए फरवरी, 2019 में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए 'परिवहन एवं विपणन सहायता' (टीएमए) योजना को लागू किया गया था और यह दिनांक 01.03.2019 से 31.03.2020 के दौरान होने वाले निर्यात के लिए उपलब्ध है।

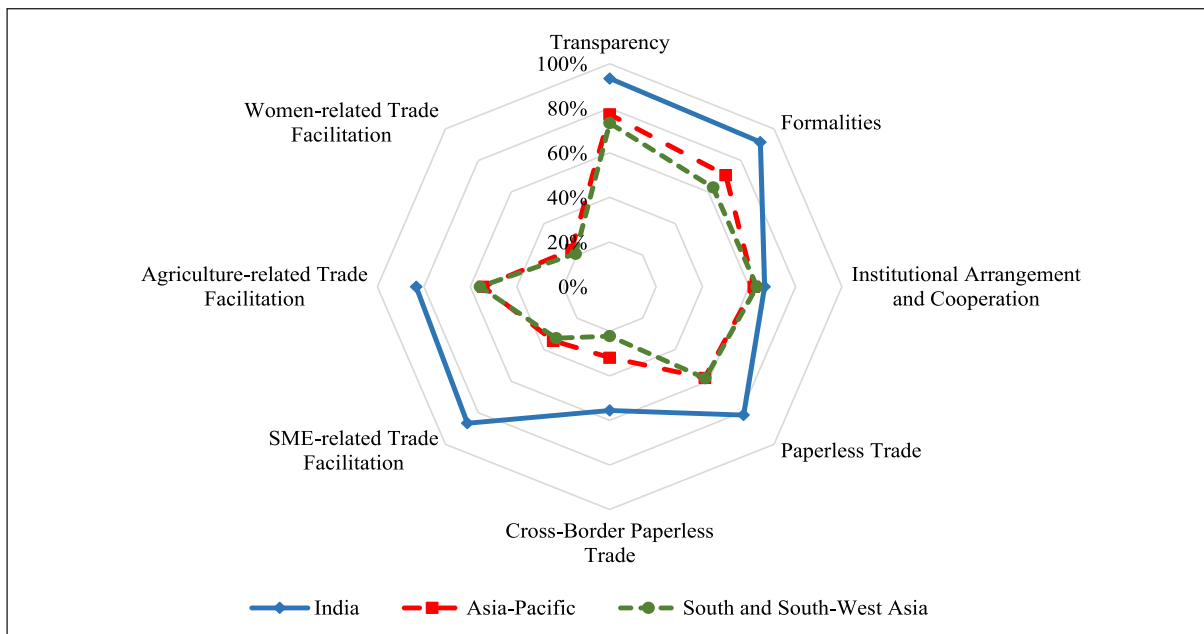
निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईईएस): भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 से निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईईएस) नामक एक योजना प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त अवसंरचना के सृजन के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता की जा सके। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। टीआईईईएस के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण एजेंसी, मुंबई में मूल के निर्धारण और प्रामाणिकता के लिए सुविधा की स्थापना और ईआईई चैन्नई एसओ विशाखापट्टनम के कार्यालय एवं प्रयोगशाला परिसर का निर्माण नामक दो परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- सीमाशुल्क पोर्टल पर व्यापार की सुविधा के लिए एकल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट) की स्थापना
- क्लियरेंस के बाद की लेखा परीक्षा
- विश्वसनीय निर्यातकों द्वारा आरएफआईडी टैग के माध्यम से स्व ई-सीलिंग
- आयात/निर्यात के लिए केवल 3 अनिवार्य दस्तावेज की अपेक्षा
- सहायक दस्तावेजों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए 'ई-संचित' प्रारंभ
- भारतीय सीमाशुल्क व्यापार करने की सुगमता डैशबोर्ड (आईसीईडीएसएच) के माध्यम से आयातित कार्गो क्लियरेंस समय की निगरानी
- 24X7 ऑनलाइन सीमाशुल्क क्लियरेंस सुविधा
- अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 'अतिथि' ऐप का प्रारंभ और
- व्यापारी समयोपति शुल्क का उन्मूलन और स्कैनर के माध्यम से ड्राइव का अधिष्ठापन

3.39 आयात के लिए सीधे बंदरगाह पर डिलीवरी (डीपीडी) एवं निर्यात के लिए सीधे प्रत्यक्ष बंदरगाह प्रवेश (डीपीई) जैसी नई योजनाओं से बंदरगाहों पर तीव्र गति से क्लियरेंस हो रही है। बंदरगाह अवसंरचना के उन्नयन, बंदरगाहों पर नए स्कैनरों के अधिष्ठापन, सुदृढ़ जोखिम आधारित उपायों के विकास एवं समस्या बड़े बंदरगाहों पर नई बंदरगाह समुदाय प्रणाली के प्रारंभ से समुद्री बंदरगाहों पर लगने वाले औसत समय में सुधार हुआ है। सीमाशुल्क 'तुरंत'⁴ (कस्टम) जैसे नए प्रयासों से सीमाशुल्क क्लियरेंस तेजी से और व्यक्तिरहित होगी।

3.40 डिजिटल एवं धारणीय व्यापार सुविधा सेवा 2019, पर अभी हाल ही में जारी किए गए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण में भारत ने न केवल अपने समग्र व्यापार सुविधा के अंकों को 69 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर लिया है अपितु एशिया-प्रशांत और दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया प्रशांत क्षेत्र (चित्र 24) में अन्य देशों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

चित्र 24: डिजिटल एवं धारणीय व्यापार सुविधा में एशिया प्रशांत एवं दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया की तुलना में भारत का प्रदर्शन (2019)



स्रोत: डिजिटल एवं सतत धारणीय सुविधाओं पर संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक सर्वेक्षण, <https://unfcsurvey.org/economy?id=IND>

4. यह अगली पीढ़ी के सुधार कार्यों का एक समूह है जिसके अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क की साफ्टवेयर प्रणालियों में एक नई सुविधा प्रारंभ की गई है जो सीमाशुल्क अधिकारियों के समक्ष अनुमोदन के लिए आयात से संबंधित दस्तावेजों को वास्तव में प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करती है। इससे समय में कमी आई है।

सारणी 15: 2018 में विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक

देश	एलपीआई में स्थान	सीमाशुल्क	अवसंरचना	अंतर्राष्ट्रीय नौवहन	लॉजिस्टिक्स सक्षमता	ट्रैकिंग एवं ट्रेडिंग	समय-सीमा
जर्मनी	1	1	1	4	1	2	3
स्वीडन	2	2	3	2	10	17	7
बेल्जियम	3	14	14	1	2	9	1
आस्ट्रिया	4	12	5	3	6	7	12
जापान	5	3	2	14	4	10	10
भारत	44	40	52	44	42	38	52

स्रोत: विश्व बैंक

क.3.4 व्यापार से संबंधित लॉजिस्टिक्स

3.41 भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है और यह एक सफल होने वाला उद्योग है। अनुमानों के अनुसार, भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर का मध्यावधि में 8-10 प्रतिशत बढ़ने की अपेक्षा है। भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग वर्तमान में लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है और 2020 तक 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की अपेक्षा है।⁵

3.42 भारतीय भंडार एवं लॉजिस्टिक बाजार को पिछले कुछ वर्षों (जनवरी, 2014 जनवरी, 2018) में लगभग 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर संस्थागत पूंजी प्राप्त हुई इस अवधि के दौरान, भंडार क्षेत्र में निवेश भू-संपदा में कुल निजी इक्विटी निवेश का लगभग 26% है लॉजिस्टिक्स परितंत्र में अनेक नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनमें से 350 स्टार्टअप्स पहले से ही पंजीकृत हैं। कृषि लॉजिस्टिक्स भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले सूक्ष्म कोल्ड स्टोर्स तैयार किए गए रहे हैं और ऐप आधारित ग्रेडिंग सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। वाहनों को अधिक ईंधन-कुशल और वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए साधान मुहैया कराने पर भी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। रोजगार पैदा करने के संदर्भ में, विशेषज्ञों का अनुमान है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर 2022 तक सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता होगा। वर्तमान

में यह सेक्टर देश में 22 मिलियन लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है

3.43 विश्व बैंक के लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स के अनुसार भारत 2014 में 54वें रैंक की तुलना में 2018 में 44वें रैंक पर ऊपर आया। लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स में विश्व के 5 उच्चतम देश तालिका -15 में भारत सहित एलपीआई में इनकी रैंकिंग ओर प्रत्येक के पृथक संकेतक सहित दर्शाए गए हैं।

3.44 व्यापार लॉजिस्टिक्स में सुधार लाने के लिए सरकार भारतमाला, सागरमाला और समर्पित माल गलियारों जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना तैयार कर रही है। परिवहन के किफायती साधनों के रूप में अंतर्देशीय जलमार्ग तैयार किए जा रहे हैं। मल्टीमॉडल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टिमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जा रहे हैं। ये 102 लाख करोड़ रूपए की लागत से तैयार होने वाले अवसंरचना परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका विवरण दिसम्बर, 2019 में सरकार द्वारा जारी किया गया है। अवसंरचना संबंधी परियोजनाएँ अगले पांच वर्षों में तैयार हो जाएंगी।

3.45 भारत सरकार राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कार्य योजना पर कार्य कर रही है। महत्वपूर्ण पण्यों की पहचान की गई है और उन्हें सबसे

5ण वाणिज्य विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार

सस्ते माध्यमों से रेलवे, तटीय मार्गों, जलमार्गों और स्लरी पाइपलाइनों जैसे अन्य माध्यमों से संचलन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। टोल प्लाजाओं पर विलम्ब में कमी लाने के लिए फास्ट टैग्स को अनिवार्य बनाया गया है। इस सेक्टर में कौशल में सुधार लाने के लिए योग्यता पैक का सृजन किया गया है। उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से अप्रेंटिस कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है/दक्षता लाने के लिए मानक तैयार किए जा रहे हैं।

3.46 लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी लाने पर सरकार जोर दे रही है। जिससे हमारे विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ड्राइविंग लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान अनुमानित स्तर 13-14 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गई, जो कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए भारत के लिए वैश्विक मानकों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ होना अनिवार्य है।

क.3.4 न्यूनमूल्यरोधी (एंटी डंपिंग) एवं संरक्षा उपाय

3.47 भारत देश में मालों के मूल्य में गिरावट कर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच आकस्मिक साठगांठ के प्रथम दृष्टया साक्ष्य वाले घरेलू उद्योगों द्वारा लाये आवेदनों के आधार पर मूल्यन्यूनरोधी अन्वेषण करता है। चीन पीआर, हांग-कांग, कोरिया, जर्मनी, इयू, यूएसए, मलेशिया, दक्षिण अफ्रिका, थाइलैण्ड, ब्राजील, इन अन्वेषणों में शामिल अन्य देश हैं।

3.48 01.04.2019 से 31.11.2019 तक की अवधि के दौरान व्यापार उपचार महानिदेशालय ने 25 मूल्यन्यूनरोधी अन्वेषण, 5 प्रतिकारी शुल्क अन्वेषण और 6 सुरक्षा अन्वेषण आरंभ किए। इस अवधि के दौरान 14 न्यूनमूल्यरोधी अन्वेषणों, 4 प्रतिकारी अन्वेषणों में अंतिम परिणाम और 5 अन्वेषणों में प्राथमिक परिणाम जारी किए गए थे।

3.49 घरेलू उत्पादकों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और शीघ्र राहत को बढ़ावा देने के प्रयासों में डी.जी.टी.आर

ने न्यून मूल्य रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क और प्रतिकारी शुल्क जैसे विभिन्न व्यापार उपायों के लिए ऑनलाइन याचिका प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पेश किया है। पोर्टल को आरटिस नाम दिया गया है। (भारतीय उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए व्यापार में उपायों के लिए आवेदन)। आवेदक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा अपने आवेदनों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3.50 डी.जी.टी.आर के अफसरों द्वारा समय समय पर उपलब्ध उपायों के बारे में विभिन्न हितधारकों को जागरूक करने के लिए 'आउटरीच' कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसके अलावा जी सी सी और जिंबावे के प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यापार उपाय तंत्र पर संगोष्ठी और पारस्परिक अनुक्रिया सत्र आयोजित किए गए। अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से उपलब्ध व्यापार उपचारात्मक उपायों के विभिन्न हितधारकों द्वारा इष्टतम उपयोग की सुविधा के लिए एक सहायता डेस्क और सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

क.4 निवल धनप्रेषण

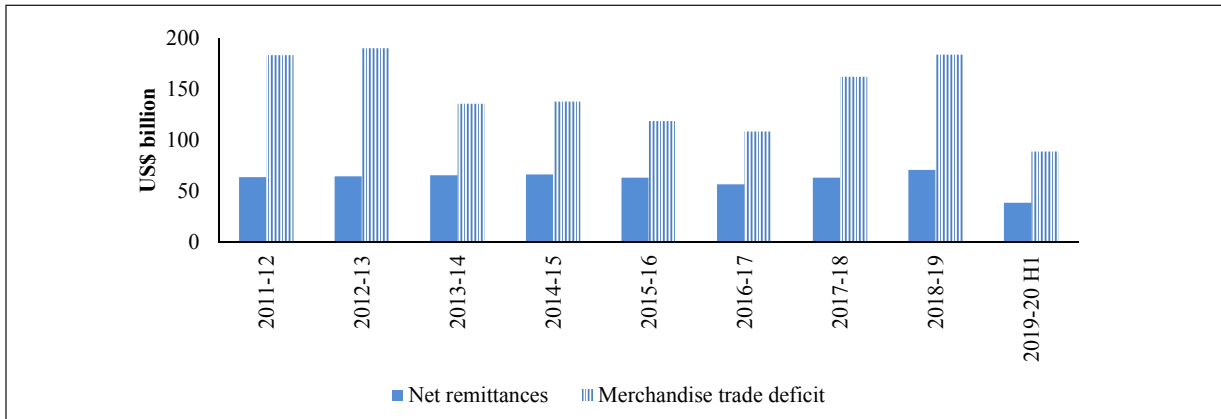
3.51 निवल प्रेषण में वृद्धि से बी ओ पी स्थिति में सुधार होता है। विदेशों में कार्यरत भारतीयों से निवल प्रेषण साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है और 2018-19 के कुल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक 19-20 की पहली छमाही में प्राप्त हुई है (तालिका 16)। कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव के संबंध में भारत में प्रेषण की चक्रीयता को आर्थिक सविक्षण, 2016-17 सहित विभिन्न अध्ययनों द्वारा अनुभविक रूप से स्थापित किया गया है (चित्र 25)।

तालिका 16: निवल धन प्रेषण
(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
298.21	319.53	70.60	38.4

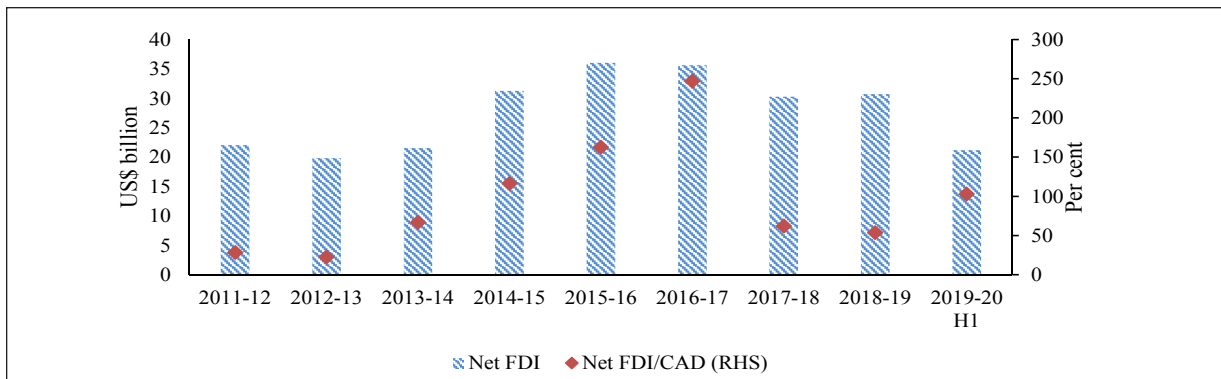
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 25 धन प्रेषण और पण्य व्यापार घाटा



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक एवं वाणिज्य विभाग

चित्र 26: निवल एफडीआई ओर सीएडी



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.52 संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 में जारी 'द माइग्रेशन रिपोर्ट' में भारत को 2019 में 17.5 मिलियन की प्रवासी ताकत के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का प्रमुख देश बताया है। विश्व बैंक की अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट की तहत, भारत 2018 में शीर्ष धन प्रेषण पाने वाला देश बना रहा, इसके बाद चीन, मेक्सिको फिलिपिन्स और मिश्र का स्थान रहा।

बी. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई)

3.53 2019-20 के शुरू के आठ महीनों में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 24.4 अमरीकी बिलियन डॉलर था। निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि से बी ओ पी स्थिति में सुधार होता है। मार्च 2014 से मार्च 2019 तक बी ओ पी स्थिति में जो प्रभावशाली सुधार आया

है, उसका मुख्य जिम्मेदार 2009-14 से 2014-2019 तक देश में निवल एफ.डी.आई. के लगभग दुगुना होना है। निवल एफ.डी.आई. का उछाल जारी रहने से पहली छमाही में ही पिछले साल से पचास प्रतिशत ज्यादा धनराशि आकर्षित हुई है (तालिका 17) देश में विदेशी निवेश के बढ़ते प्रवाह के लिए एफ.डीआई दिशानिर्देशों का लगातार उदारीकरण जिम्मेदार रहा है।

तालिका 17: निवल एफडीआई (यूएस डालर बिलियन में)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
92.51	163.87	30.7	21.3

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.54 निवल एफ.डी.आई. में वृद्धि सीएडी के निधिकरण का एक अधिक उपयुक्त स्रोत प्रदान करती है, और इस लिहाजे से अन्य पूंजी प्रवाह की तुलना में बीओपी स्थिति में सुधार के लिए अधिक स्थिरता प्रदान करती है। देश में 2019-20 की प्रथम छः माही में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा चालू खाता घाटे का वित्तीय 2018-19 की समतुल्य अवधि से अधिक रहा है। (चित्र 26)

सी. विदेशी पत्रक निवेश (एफ पी आई)

3.55 देश में वर्ष 2019-20 के पहले 8 महीनों में निवल एफपीआई प्रवाह 12.6 बिलियन अमेरीकी डालर रहा निवल एफ.पी आई प्रवाह में वृद्धि से बी ओ पी स्थिति में सुधार होता है और प्रत्यक्ष निवेश या आरक्षित संपत्तियों में के अलावा, सीमा पर लेनदेन में शामिल ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियों के कारण उत्पन्न हुई है। किन्तु एफ.पी आई को अक्सर उसकी, एक अर्थव्यवस्था में मुसीबत के पहले संकेत पर या दुनिया में कहीं और विशेष रूप से अमरिका में फेडरल रिजर्व के हाथों निवेश आकर्षण में बढ़ावा देखकर भाग

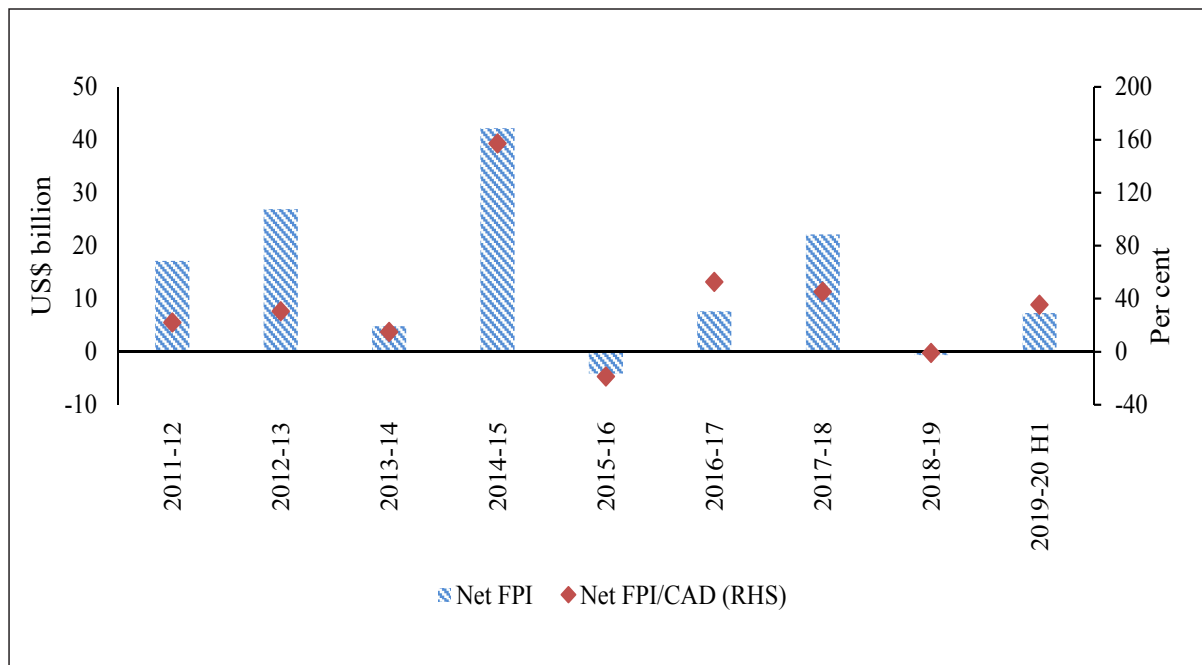
जाने की प्रवृत्ति के कारण 'हॉट मनी' कहा जाता है। 2009-14 की 45.6 प्रतिशत की तुलना में 2014-19 की 17.1 प्रतिशत, निवल एफडीआई के संबंध में, सी ए डी को वित्त प्रदान हेतु निवल एफ पी आई पर निर्भरता कम है (चित्र 27)। 2018-19 में देश से निवल पोर्टफोलियो बहिर्वाह रहा जिसे भारत की आर्थव्यवस्था पर निवेशकों के विश्वास की कमजोरी के रूप में देख गया। हालांकी 2019-20 प्रथम छमाही में पोर्टफोलिया प्रवाह का सकारात्मक बनने के लिए अमेरिका की मौद्रिक नीति, वैश्विक बाजार में तरलता में वृद्धि और बजट घोषणा के पश्चात भारत के विकास की प्रबल संभावनाओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है (तालिका 18)।

तालिका: 18 निवल एफ पी आई
(बिलियन अमेरीकी डालर)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
59.1	67.18	-0.62	7.3

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 27: निवल एफपीआई ओर सीएडी

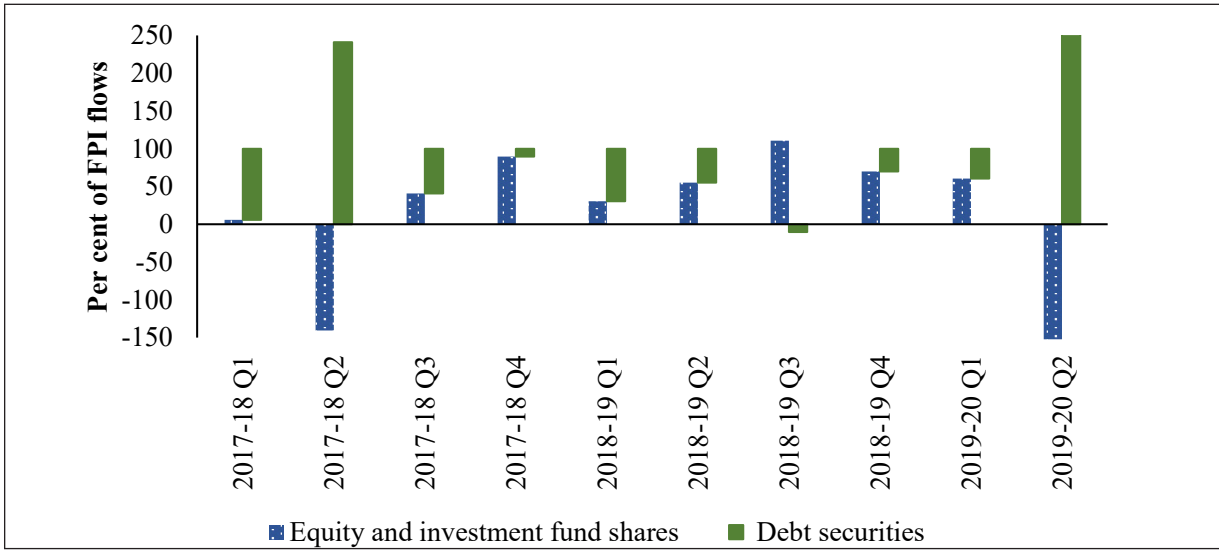


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.56 बाहरी ऋण की सेवा को प्रभावित करने के मामले में निवल एफ पी आई की ऋण-इक्विटी रचना मायने रखती है। एक कम ऋण घटक, ऋण सर्विसिंग के बोझ

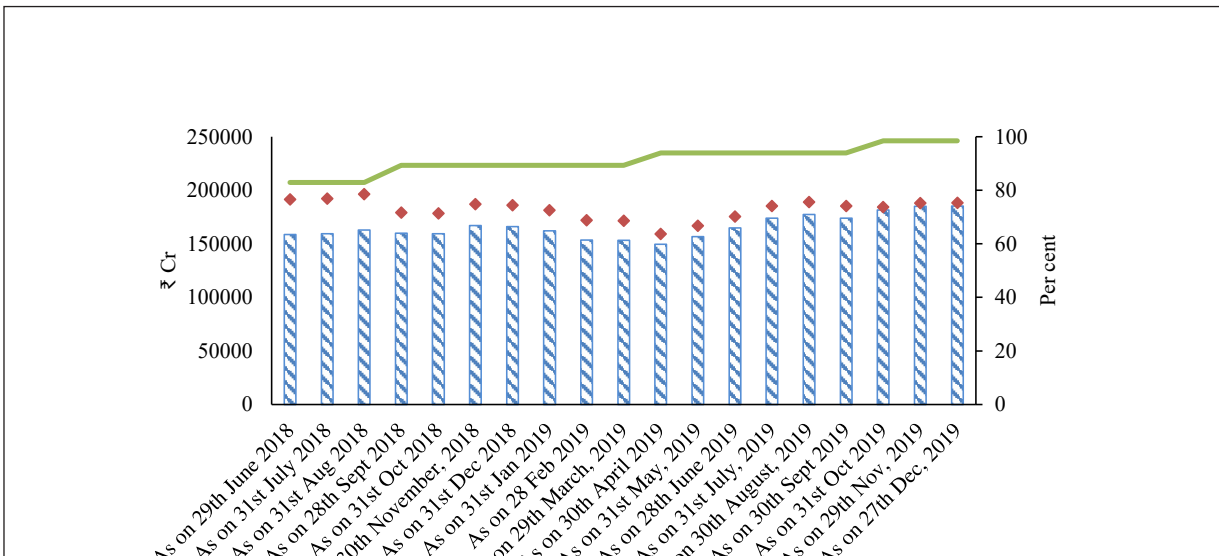
को कम करना है और बी ओ पी स्थिति में सुधार करता है। 2019-20 तक हाल की तिमाहियों में, एफ पी आई की संरचना में बदलाव इक्विटी और निवेश फंड बनाने

चित्र 28: एफ पी आई प्रवाह की संरचना



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 29: सरकारी प्रतिभूतियों में एफ पी आई



स्रोत: भारतीय आशोधन निगम (सीसीआइएल)

वाली अधिक गैर-ऋण रचना की ओर चला है। दूसरी तरफ, डेब्ट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश में बढोत्तरी, देश के ऋण बाजार को गहरा बनाने के लिए जरूरी है (चित्र 28)।

3.57 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवम्बर, 2019 में प्रकाशित 2018-19 में भारत के भुगतान शेष के मूल्यांकन संबंधी एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ऋण खंड में सर्वाधिक एफ पी आई बहिरवाहि सरकारी क्षेत्र (अर्थात, सरकारी प्रतिभूतियों) से हुआ। इस संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों में एफ पी आई की निवेश सीमाओं में वृद्धि करने और न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता को सुगम बनाने की हालिया

सरकारी पहलों से एफ पी आई प्रवाहों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। अप्रैल, 2018 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों) में एफ पी आई निवेश की सीमा संशोधित की थी जिसमें सीमा को प्रत्येक वर्ष 0.5 प्रतिशत तक बढ़ाकर 2018-19 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 5.5 प्रतिशत तक और 2019-20 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 6 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के आधार पर, सरकारी प्रतिभूतियों में एफ पी आई सीमाओं की उपयोग दर मार्च, 2019 में 68.6 प्रतिशत से बढ़ाकर

दिसम्बर, 2019 में 75.6 प्रतिशत कर दी गई (चित्र 29)।

घ. विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

3.58 निवल विदेशी वाणिज्यिक उधारों में वृद्धि से भुगतान शेष की स्थिति में सुधार तो होता है किन्तु इससे 2009-14 में स्वस्थ सकारात्मक स्तर से 2014-19 के दौरान ऋणात्मक होने पर भुगतान शेष की स्थिति बदतर हो गई (तालिका 19)। तथापि, 2018-19 में निवल ईसीबी में उछाल आया और 2019-20 का पहली छमाही में देश में लगभग इतनी ही राशि का पहले ही प्रवाह हो चुका है।

तालिका 19: निवल विदेशी वाणिज्यिक उधार (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
42.80	-4.24	9.77	9.76

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

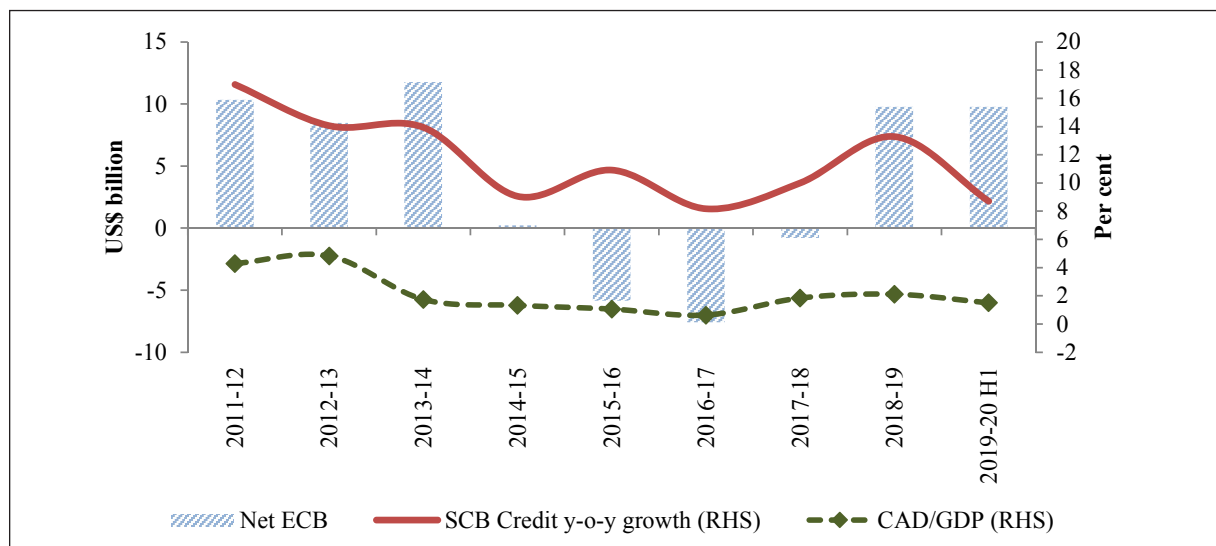
3.59 जबकि हालिया वर्षों में घरेलू बैंक ऋण वृद्धि में गिरावट आई है, 2017-18 से ईसीबी मार्ग के जरिए ऋण में अत्याधिक वृद्धि देखने में आई है। ईसीबी मार्ग के लिए कारपोरेट की बढ़ती तरजीह का कारण निम्न वैश्विक ब्याज दरें और विदेश में बेहतर तरलता हो सकता है (चित्र 30)। इसके अतिरिक्त, ईसीबी के उदारीकरण, ईसीबी की सभी कीमत का समाहन, योग्य उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार, 750 मिलियन अमरीकी डालर तक सभी योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्षेत्रवार उधार सीमाओं को हटाने के प्रति भारत सरकार द्वारा हाल ही में बहुत सारे उपाय

शुरू किये गए हैं, तथा 10 बिलियन अमरीकी डालर तक कार्यशील पूंजी जुटाने हेतु तेल कंपनियों को अनुमोदन ने ईसीबी की आकर्षकता बढ़ायी है।

3.60 ईसीबी मार्ग की उपलब्धता तथा इसकी लगातार आसानी से उपलब्धता इस दावे पर प्रश्न उठाती है कि क्या राजकोषीय घाटे में बढ़ोत्तरी निधि की आवश्यकता के लिए निजी निवेश को बाजार से बाहर कर देती है खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी बचत हमेशा उपलब्ध होती है तथा भारत एफडीआई तथा ईसीबी आकर्षित करने के द्वारा इससे लाभान्वित हुआ है। इस संदर्भ में, यदि 2014-19 के दौरान नियत कारपोरेट निवेश दर नहीं बढ़ी तो यह इसलिए नहीं था क्योंकि बजट उधारियों सहित सरकार की संपूर्ण निवल उधारियों बैंको से कारपोरेट क्षेत्र को ऋण सुलभता में बाधक हो गई थी। यह एक कारण रहा होगा कि कारपोरेट क्षेत्र आसानी से ईसीबी को प्राप्त कर सका जैसाकि इसने 2017-18 के पश्चात् किया था। नियत निवेश मंद निवेश दृष्टिकोण के कारण नहीं बढ़ा था, तथा जैसे ही निवेश दृष्टिकोण में सुधार हुआ वैसे ही इसकी दर में भी सुधार हुआ जोकि लगातार ईसीबी द्वारा वित्त पोषित हो रहा था।

3.61 यद्यपि, खुली अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे से निजी निवेश को बाहर नहीं किया जा सकता है यह दो अपरिहार्य समस्याएं अवश्य खड़ी करता है। पहला, यह कारपोरेट को घरेलू बाजार में उनके अधिक निवेश करने का प्रलोभन देते हुए पूंजी की घरेलू लागत को बढ़ाता है जब वे ईसीबी के जरिए अपने निवेश में वित्त पोषण करने के लिए मांग करते हैं। साथ ही यह विदेश

चित्र 30. ईसीबी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) ऋण (वर्षानुवर्ष) तथा सीएडी



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

में निम्नतम ब्याज दर साथ ही हेजिंग की लागत का पूंजी की घेरलू लागत से कम होने में परिणत होता है। दूसरा, उच्चतर राजकोषीय घाटा कारपोरेट को विदेशी बचत की अधिक राशि मांगने पर मजबूर करता है जिससे चालू खाता घाटा बढ़ता है, देश को दोहरे घाटे की चुनौतियों के समीप लाता है, जहाँ निवेशक आत्मविश्वास को छोटा सा नुकसान भी पूंजी पलायन तथा रूपये की तीव्र गिरावट में परिणत हो सकता है। इस परिस्थिति में, भुगतान शेष में असाहयता अधिक संभाव्य बन जाती है।

ड विदेशी ऋण

3.62 जीडीपी अनुपात की तुलना में वैदेशिक ऋण में वृद्धि ऋण की अदायगी तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर आहरण को बढ़ाती है, जिससे भुगतान संतुलन बिगड़ता रहा है। 2009-2014 की तुलना में 2014-2019 में प्रमुख गिरावट के पश्चात् जीडीपी की तुलना में भारत का वैदेशिक ऋण वाणिज्यिक उधारियों, गैर निवासियों द्वारा की गई जमाओं तथा लघु आवधिक व्यापार ऋण में बढ़ोत्तरी के कारण मुख्य रूप से मार्च अंत 2019 के अपने स्तर से 2020 की पहली छमाही के अंत तक 0.3 प्रतिशत थोड़ी सी बढ़ गई थी (तालिका 20 और चित्र 31)। तथापि, यह बढ़ोत्तरी आंशिक रूप से भारतीय रूपये के अमरीकी डालर तथा 2019-20 की दूसरी तिमाही में प्रमुख मुद्राओं के प्रति अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि द्वारा हुई थी। विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी, 2020 के अनुसार भारत का विदेशी ऋण सभी विकासशील देशों के

जीडीपी के साथ अनुपात की तुलना में (25.6 प्रतिशत) की तुलना में निम्न बना रहा।

तालिका 20: विदेशी ऋण (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
23.9	19.7	19.8	20.1

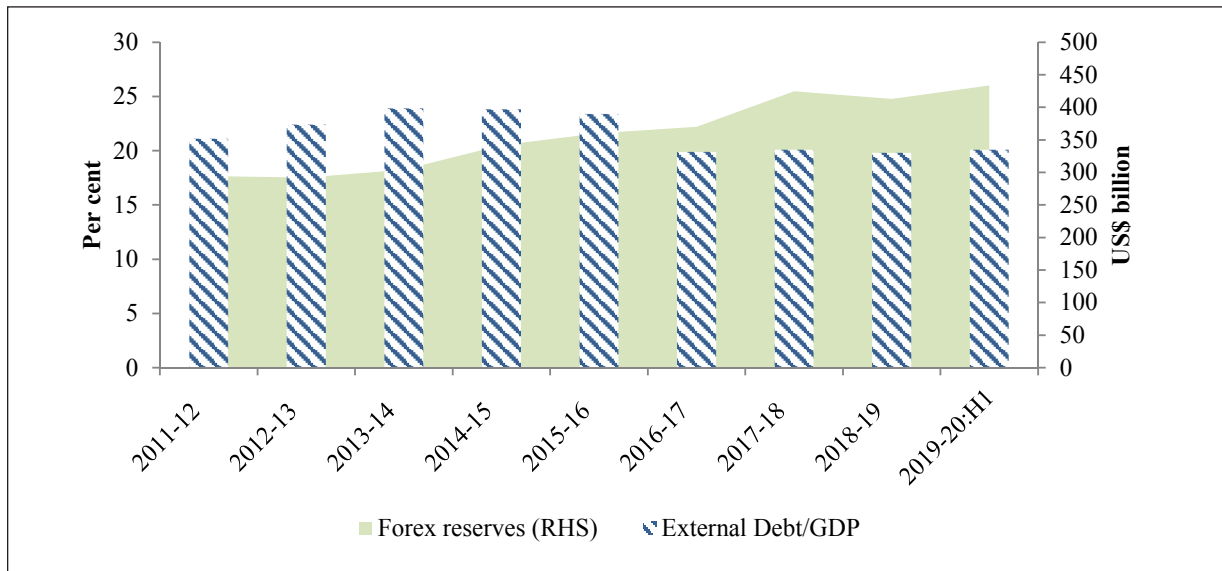
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

3.63 लघु अवधि ऋण का बढ़ता हुआ हिस्सा भुगतान संतुलन की स्थिति और अधिक कमजोर कर देता है क्योंकि ऐसी उधारियों में अपेक्षाकृत ब्याज की दर उच्च होती है। तथापि, 2012-13 से कुल वैदेशिक ऋण में लघु ऋण (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ) के हिस्से देखा जा सकता है (चित्र 32)। ऐसे समय पर जबकि तेजी से नहीं बढ़ रहा है तथा उच्च ब्याज दर पर ऋण भविष्य में भुगतान संतुलन पर दबाव सृजित कर सकता है।

च. वैदेशिक देनदारियां (ऋण इक्विटी)

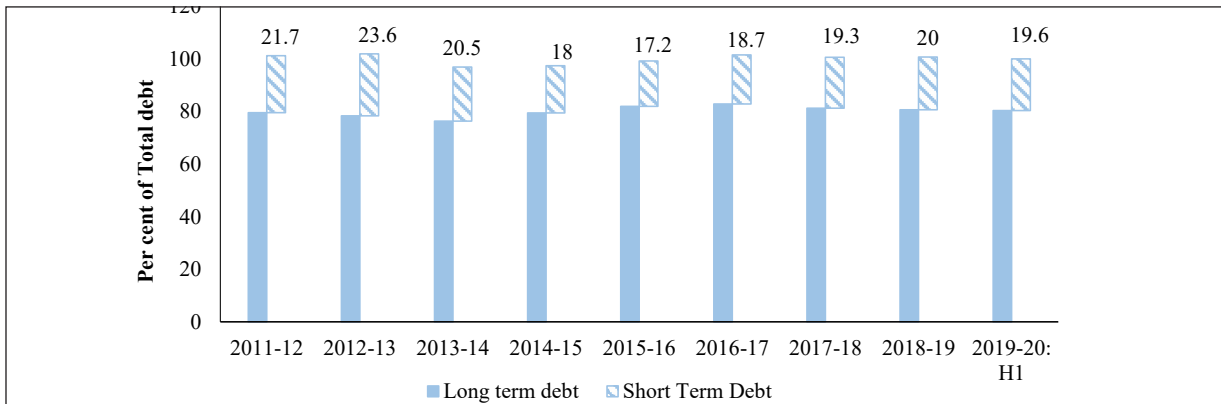
3.64 जीडीपी के अनुपात में वैदेशिक देनदारियाँ (ऋण इक्विटी) वैदेशिक देनदारियों का अधिक व्यापक पैमाना है क्योंकि यह लाभांश अदायगी और ब्याज को जोड़ता है। इस अनुपात में बढ़ोत्तरी बहुत हद तक विदेशी मुद्रा भंडार का गिराती है तथा भुगतान स्थिति को बिगाड़ता है। एफ पी आई तथा एफ डी आई दोनों के भीतर

चित्र 31: विदेशी ऋण/जीडीपी तथा विदेशी मुद्रा भंडारण



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

चित्र 32: लघु अवधि वैदेशिक ऋण



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, तिमाही वैदेशिक ऋण रिपोर्ट, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

ईक्विटी निवेश को मिला लेना भुगतान संतुलन स्थिति की कमजोरी को बना सकता है। जीडीपी के अनुपात में भारत की वैदेशिक देनदारियों में 2009-14 की तुलना में 2014-19 के दौरान प्रमुख गिरावट देखी गई है (तालिका 21 और चित्र 33)। साधारण वैदेशिक ऋण स्तर के बावजूद 2019-20 की पहली तिमाही में इस अनुपात में हाल ही की वृद्धि यह इंगित करती है कि कुल वैदेशिक देनदारियां ईक्विटी के प्रति सिकुड़ी हैं। यह एफडीआई एवं एफपीआई अंतर्वाह में बढ़ोत्तरी के कारण हो सकती है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा ईक्विटी के द्वारा बना हुआ होता है। ईक्विटी में विदेशी निवेश पर लाभांश अदायगी के रूप में गैर ऋण देनदारियों में बढ़ोत्तरी भुगतान संतुलन पर दबाव देगा। तथापि, दूसरी ओर ऐसे निवेश भविष्य के धन सृजन की क्षमता रखते हैं तथा यदि लाभांश अदायगी

देश में वापस लगा दी जाए तो। भुगतान संतुलन पर दबाव कुछ हद तक हटाया जा सकता है

तालिका 21: वैदेशिक देनदारियां (ऋण, ईक्विटी) जीडीपी (समयावधि अंत)

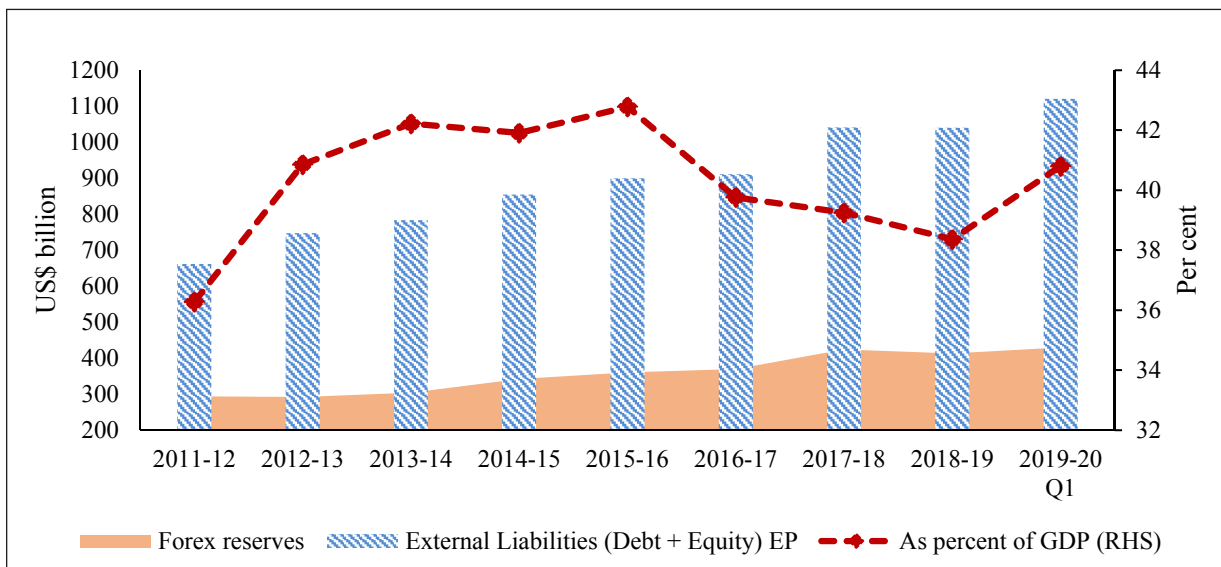
2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 Q1
42.2	38.2	38.4	40.8

स्रोत: आई एस एफ (नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर)

छ: निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (एन आई आई पी)

3.65 निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति किसी विनिर्दिष्ट समय पर उस राष्ट्र की विदेशी संपत्तियों के

चित्र 33: वैदेशिक देनदारियां (ऋण, ईक्विटी) अवधि-अंत (ईपी) पर



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, आई एम एफ (नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर)

भंडार तथा उस राष्ट्र कर आस्तियों के विदेशी भंडार के बीच अंतराल को मापता है। एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात में बदलाव देश द्वारा वहन की गई वैदेशिक देनदारियों से विदेशी देश द्वारा किए गए निवेश का निवल प्रभाव है जिसके द्वारा ऋण में निवल बदलाव को मापना तथा जीडीपी के संबंध में ईक्विटी शोधन भार पर मापा जाता है। 2009-14 से 2014-19 तक निवल एफडीआईपी स्तर से बिगड़ी है (तालिका 22)। हाँलाकि, जीडीपी के संबंध में भार कम हुआ है तथा

: ऋण एवं ईक्विटी शोधन दायित्व भी कम हुए हैं। 2019-20 की पहली छमाही के अंत पर एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात 2018-19 के अंत में जिनता था उतना ही बना रहा (चित्र 34)।

संभावी परिदृश्य

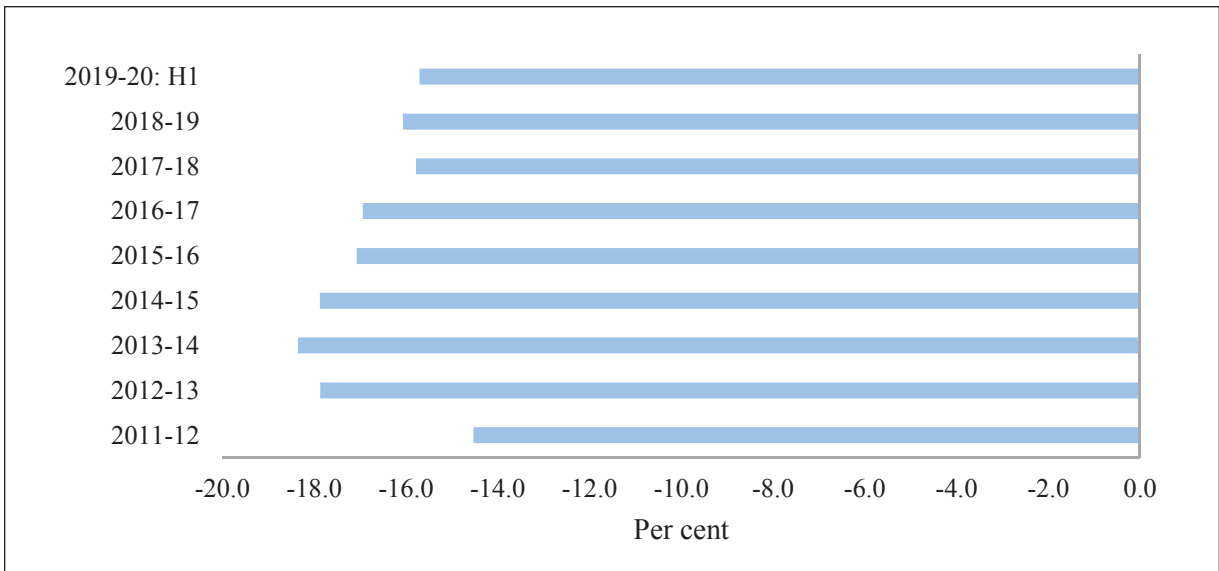
3.66 2018-19 में कमजोरियों में बढ़ोत्तरी को देखने के पश्चात्, जिसने विदेशी मुद्रा भंडार की साधारण गिरावट की थी, भारत के वैदेशिक क्षेत्र ने भुगतान संतुलन

तालिका 22: निवल आईआईपी (अवधि अंत पर)

मद	2009-14	2014-19	2018-19	2019-20 H1
एनआईआईपी (बिलियन अमरीकी डालर में)	-340.8	-436.8	-436.8	-436.7
एनआईआईपी/जीडीपी	-18.4	-16.1	-16.1	-15.7

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 34: निवल आईआईपी/जीडीपी

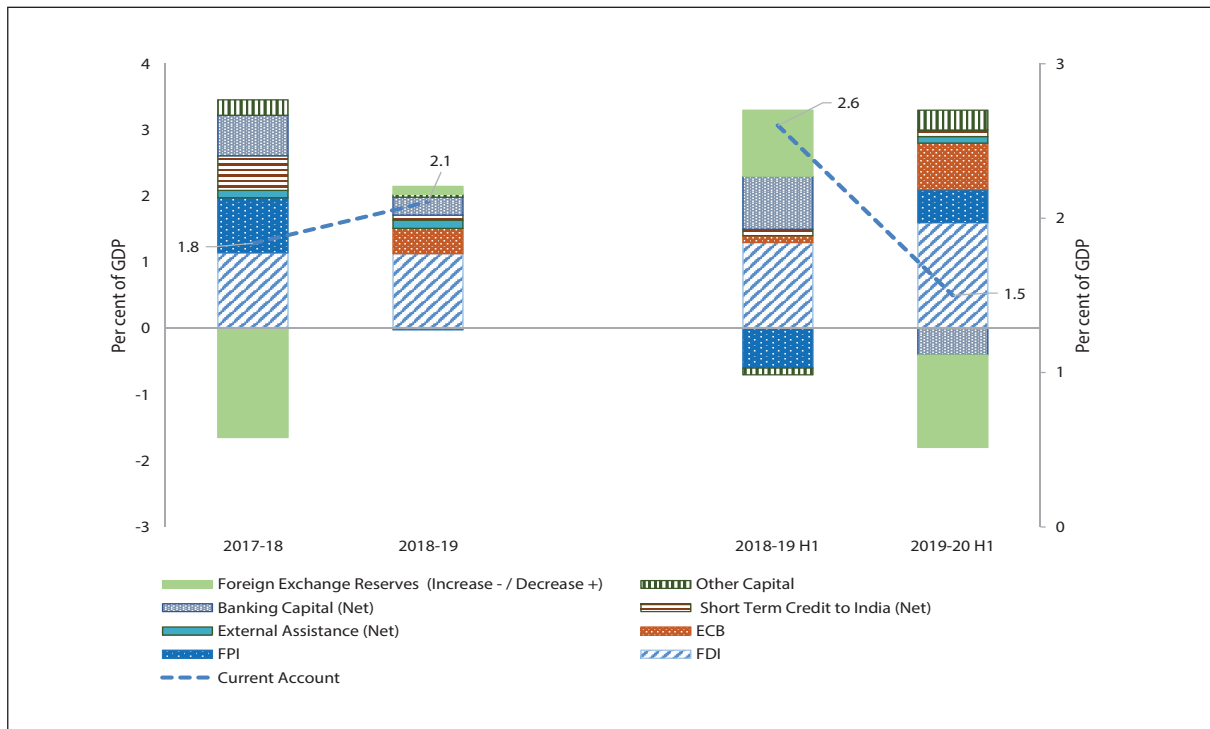


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

की स्थिति में सुधार के साथ 2019-20 की पहली छमाही में स्थिरता प्राप्त की थी जो कि एफडीआई, एफपीआई एवं ईसीबी, मजबूत धनप्रेषण की प्राप्ति तथा जीडीपी के अनुपात में सीएडी के संकुचन के जरिए पूंजी प्रवाह की हालत सुधरने का परिणाम थी। वैदेशिक ऋण जीडीपी के 20 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है। 10

जनवरी 2020 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2019-20 की पहली छमाही में 27.5 बिलियन अमरीकी डालर की अभिवृद्धि दर्ज करते हुए 461.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गई कई वर्षों विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव का सारांश अनुलग्नक-III में दिया गया है (चित्र 351)

चित्र 35: चालू खाता घाटा का वित्त पोषण



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

3.67 हाल ही में भारत का सीमा शुल्क प्रबंधन व्यापारिक सहयोगियों के चलते दबाव में है जो देश के मूल सीमा शुल्क में कटौती चाहते हैं। भारत ने अपने सीमा शुल्क प्रबंधन का यह कहते हुए बचाव किया है कि भारत के संवेदनशील कारोबार को संरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है। यद्यपि व्यापारिक सहभागियों से अलग भारत सरकार इस बात से परिचित है कि वर्तमान के विपरीत शुल्क-ढांचे को ठीक करने के लिए मध्यवर्ती आदानो एवं कच्चे माल के संबंध में शुल्क दरों को कम करना पड़ सकता है। समन्वित शुल्क ढांचे से निर्यात के विनिर्माण के लिए आयातित माध्यमिक

आदान की लागत कम होगी जिससे देश का निर्यात और अधिक प्रतियोगी बनेगा। निर्यात की परिणामी वृद्धि से भारत की बीओपी स्थिति में सुधार आएगा। बाक्स 2 में यह चर्चा की गई है कि प्रत्येक बार मध्यवर्ती आदान का भारतीय आयात बढ़ा है, ताकि सबद्ध उपभोग वस्तुओं का निर्यात हो सके। तदनुसार, मध्यवर्ती आदान के मूल सीमा शुल्क की कटौती से न केवल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रोत्साहन सृजित कर वाला विपरीत शुल्क ढांचा सही होगा बल्कि उन उपभोग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि भी होगी जो आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं का अधिक प्रयोग करती है।

बाक्स-2: निर्यातों की आयात लोच शीलता

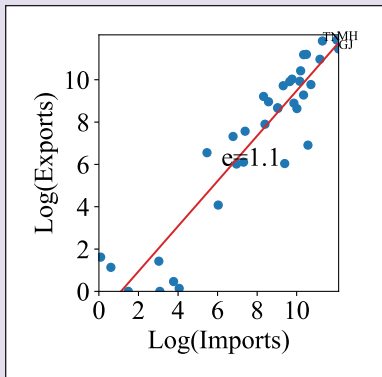
यहां तैयार माल के निर्यात और कच्चे माल व मध्यवर्ती वस्तुओं के आपात के बीच संबंध का विश्लेषण किया जा रहा है। कच्चे (मध्यवर्ती पदार्थ) उन चीजों का उत्पादन करने के लिए आयात किए जाते हैं जिन्हें आंतरिक रूप से उपभोग और निर्यात भी किया जा सकता है (उदाहरण के लिए ट्रकों का निर्माण करने के लिए ट्रांस एक्सल आयात किए जाते हैं; आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण का आयात होता है। यह विश्लेषण अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 के ई-बे बिलों के आंकड़ों पर आधारित है। विश्व समेकित व्यापार तन्त्र खडब्ल्यूआईटीएस, के उत्पाद स्तरीय वर्गीकरण का प्रयोग किया गया है— अर्थात् कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं के उत्पादन स्तर वर्गीकरण का प्रयोग 4 अंकीय स्तर पर इस डाटा को

आगे उपयोग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, चमड़ा क्षेत्र में डब्ल्यू आईटी एस उत्पाद स्तर वर्गीकरण का प्रयोग 4 अंकीय स्तर पर कच्चा माल मध्यवर्ती वस्तुओं एवं उपभोक्ता/पूँजीकृत वस्तुओं की पहचान करने के लिए अध्याय 41,42 और 43 के इस तन्त्र के कोड प्रयोग किए गए हैं। चार-अंकीय स्तर पर ई वे बिल उत्पाद स्तर डाटा भी उपलब्ध है। ऑटोमोबाइल एवं औषधि जैसे क्षेत्रों के लिए रिसर्च पेपर एवं रिपोर्टों का प्रयोग किया गया है जिन्होंने कच्चा माल एवं तैयार वस्तुओं को 4 अंकीय स्तर पर वर्गीकृत किया है।

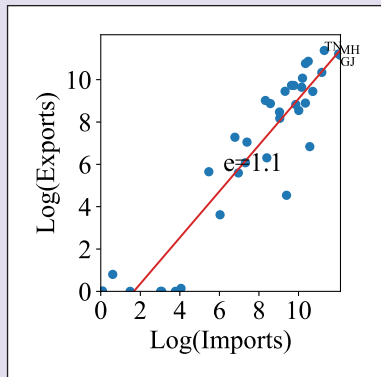
भारत में, एकीकृत स्तर पर, निर्यात की आयात लोच (चित्र के में दर्शाए अनुसार) 1.1 है। अर्थात् कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात में 1% वृद्धि से तैयार वस्तुओं के निर्यात में 1.1% वृद्धि होती है। चित्र 'ख' और 'ग' में यह दर्शाया गया है कि उपभोक्ता वस्तुओं एवं पूँजीगत वस्तुओं के निर्यात की लोच क्रमशः 1.1 एवं 0.9 हैं। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात कच्चा माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात, पूँजीगत वस्तुओं की तुलना में अधिक संवेदनशील है।

निर्यात की आयात लोच

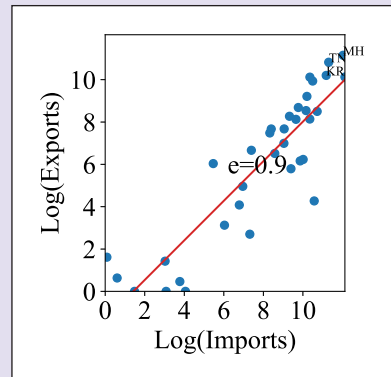
चित्र क: एकीकृत



चित्र ख: उपभोक्ता वस्तुएं



चित्र ग: पूँजीगत वस्तुएं



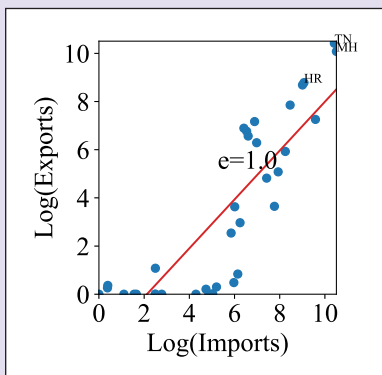
स्रोत: ई-वे बिल डाटा एवं सर्वोत्तम परिकलन
टिप्पणी: अध्याय 10 से 99 पर आधारित

क्षेत्र वार विश्लेषण

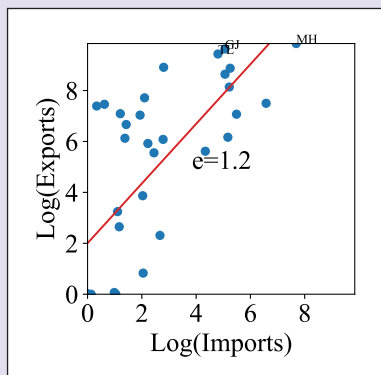
क्षेत्रवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि ऑटो मोबाइल, मोटर साइकिल, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, औषधि उत्पाद, मशीनरी, परिधान की मदें, जूते जैसे क्षेत्रों विविध विनिर्मित वस्तुएं जैसे खिलोने एवं कुशन, ग्लासवेयर एवं सिरामिक उत्पाद, आरिस्टकल यंत्र, बायलर्स, स्टेनलेस स्टील एवं स्विच की आयात लोच 1 से अधिक है। चित्र ध में कुछ क्षेत्रों की आयात लोच को दर्शाया गया है।

चित्र ध: 1 से अधिक निर्यात की महत्वपूर्ण लांच वाले क्षेत्र

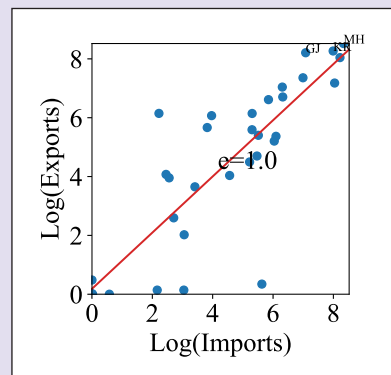
ऑटोमोबाइल



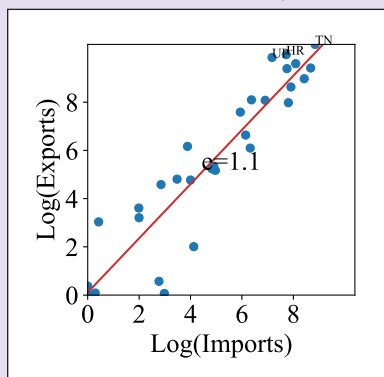
औषधि निर्यात



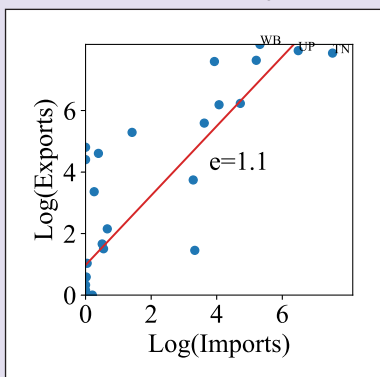
मशीनरी



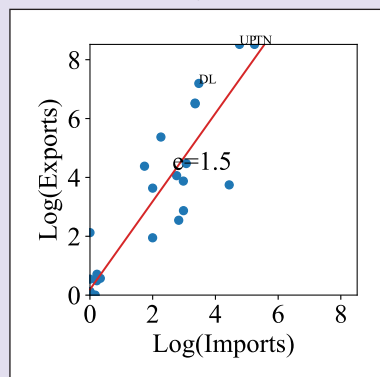
परिधान की वस्तुएं



चमड़े की वस्तुएं



जूते



स्रोत: ई-वे बिल एवं सर्वेक्षम परिकलन

यह दर्शाता है कि संवर्धित मूल्य के माध्यम से भारत इन क्षेत्रों में कच्चा माल का आयात करके संसाधित तैयार उत्पाद का निर्यात कर रहा है।

क्षेत्र	कच्चा माल/मध्यवर्ती वस्तुएं	तैयार वस्तुएं
ऑटो मोबाइल	चैसिस, बॉडीज ऑटो पार्ट्स एवं उपसाधन, वलनीकृत रबड़ की ट्यूब एवं पाइप, सुरक्षा ग्लास	टैक्टर, मोटर वाहन डम्पर विशेष प्रयोजनी वाहन मोटर साइकिल
औषधि	एन्टीसेरा वैक्सीन, प्रतिरक्षा उत्पाद, पशु उत्पत्ति की औषधि जिनकी खुदरा बिक्री नहीं है।	खुदरा बिक्री के लिए दवाईयां एवं औषधियां,
मशीनरी	शेवर्स के पार्ट, विद्युत ट्रांसफार्मर, प्राइमरी सैल	परिधान, डिश, वाइंग मशीन, वाशिंग मशीन, वैक्यूमक्लीनर, ओवन, फिले लैंप डीसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर
परिधान की वस्तुएं	कॉटन, सिल्क यार्न, ऊन, ऊनी कपड़ा, सशिलस्ट स्टैपल फायबर, जूट	सैनेटरी तौलिया, कारपेट, वस्त्र, वॉल कवरिंग, कम्बल, शाल, मैट्रेस
चमड़े की वस्तुएं	पशुओं की खाल एवं पशु का चमड़ा	ट्रंक, हैण्ड, दस्ताने, जैकेट, बैल्ट
जूते	चमड़े की सोल, शीप लाइनिंग, छतरी फेम, फैल्ट हेट फार्म एवं बॉडीज	जूते, टोपियाँ, छाते

स्रोत: विश्व एकीकृत व्यापार समाधान (डब्ल्यू आई टीएस) (बड़े इंडीपेंडेड ट्रेड सॉल्यूशन)

भारत इन क्षेत्रों में की मूल्य श्रृंखला में प्रगति कर रहा है। इसे और आगे सहायता करने के लिए यह आवश्यक है इन क्षेत्रों के मध्यवर्ती आदान के मूल सीमा शुल्क को कम कर के कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात को सरल बनाएं। इससे न केवल विपरीत शुल्क संरचना सही होगी बल्कि इससे विनिर्माण, रोजगार उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के संवर्धन के लिए उचित प्रोत्साहन भी सृजित होगा।

अध्याय एक नजर में

- भारत की भुगतान संतुलन (बीओपी) की स्थिति में, मार्च, 2019 के अंत में, फोरेक्स रिजर्व में 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में सितंबर, 2019 के अंत में 433.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सुधार देखा गया जिसे चालू खाता घाटे (सीएडी) के संकुचन से स्थिरता मिली जोकि वर्ज 2018-19 में 2.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी, 2020 को यथास्थिति, 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- वर्ष 2019 में वैश्विक में 2.9 प्रतिशत की प्राक्कलित वृद्धि दर के अनुरूप वैश्विक व्यापार में, वर्ष 2017 की 5.7 प्रतिशत की चरम स्थिति के बाद, 1.0 प्रतिशत की वृद्धि का प्राक्कलन किया गया है। हालांकि, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के पुनःस्थापन के साथ वर्ष 2020 में इसके 2.9 प्रतिशत तक भरपाई करने की आशा है।
- वर्ष 2009-14 से वर्ष 2014-19 के दौरान भारत के वाणिज्यिक व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है यद्यपि बाद की अवधि में अधिकांश सुधार वर्ष 2016-17 में क्रूड की कीमतों पचास प्रतिशत से अधिक की गिरावट के कारण हुआ है।
- पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, औषधीय फार्मूले एवं जीव-वैज्ञानिक मर्दें, स्वर्ण और अन्य कीमती धातुएं शीर्ष निर्यातित वस्तुएं बनी हुई हैं। क्रूड पेट्रोलियम, स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कोक एवं ब्रिकेट शीर्ष आयातित मर्दों में शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूईई, सऊदी अरब और हांगकांग भारत के पांच शीर्ष व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं।
- जीडीपी के सामेक्षतः भारत का निवल सेवा अधिशेष निरंतर कम हो रहा है। पिछले दो वर्षों में आधे से कम की गिरावट से पूर्ण वर्ष 2016-17 में इसने दो तिहाई व्यापार घाटे का वित्तपोषण किया।
- व्यापारिक सुविधाकरण के तहत विश्व बैंक की निगरानी में इसकी व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट में लगभग 190 देशों के समग्र श्रेणी निर्धारण के अंतर्गत “ट्रेडिंग एक्सेस बॉर्डर्स” संकेतक के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2016 में अपनी 143 वीं रैंकिंग में सुधार करके वर्ष 2019 में 68वीं रैंक प्राप्त की है।
- भारत की प्रचालन संबंधी (लॉजिस्टिक्स) उद्योग वर्तमान में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आस-पास प्राक्कलित किया गया है और वर्ष 2020 तक इसके 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है।
- विदेशों में नियोजित भारतीयों से प्राप्त धनप्रेषणों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हो रही है और वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में भी यह प्रक्रिया जारी है जहां प्राप्त धनराशि विगत वर्ष के स्तर से पचास प्रतिशत से अधिक है।
- वर्ष 2019-20 में निवल एफडीआई अंतर्प्रवाह वृद्धिशील बने हुए हैं और प्रथम आठ माह में 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित हुआ जोकि वर्ष 2018-19 की संगत अवधि की तुलना में उच्चतर है। वर्ष 2019-20 के प्रथम आठ माह में निवल एफपीआई 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया।
- सितंबर, 2019 के अंत में यथास्थिति, विदेशी ऋण जीडीपी के 20.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर है। वर्ष 2014-15 से अच्छी-खासी गिरावट देखने के बाद, भारत की वैदेशिक देयताओं (ऋण एवं इक्विटी) में जीडीपी के संदर्भ में जून, 2019 के अंत में यथास्थिति, वृद्धि है जिसके मुख्य कारणों तौर पर एफडीआई, पेरिफालियों प्रवाहों और विदेशी वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) में वृद्धि का उल्लेख किया जा सकता है।

भुगतान शेष

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

क्र. सं.	मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19	2019-20
							अप्रैल-सित	अप्रैल-सित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I चालू खाता								
1	निर्यात	3,16,545	2,66,365	2,80,138	3,08,970	3,37,237	1,66,788	1,62,743
2	आयात	4,61,484	3,96,444	3,92,580	4,69,006	5,17,519	2,62,575	2,47,037
3	व्यापार संतुलन (1-2)	-1,44,940	-1,30,079	-1,12,442	-1,60,036	-1,80,283	-95,788	-84,294
4	अदृश्य (निवल)	1,18,081	1,07,928	98,026	1,11,319	1,23,026	60,931	63,673
	क. सेवाएं	76,529	69,676	68,345	77,562	81,941	38,932	40,474
	ख. आय	-24,140	-24,375	-26,302	-28,681	-28,861	-14,363	-14,739
	ग. अंतरण	65,692	62,627	55,983	62,438	69,946	36,362	37,938
5	माल और सेवा संतुलन	-68,411	-60,402	-44,098	-82,474	-98,342	-51,240	-43,820
6	चालू खाता शेष (3+4)	-26,859	-22,151	-14,417	-48,717	-57,256	-34,857	-20,621
II पूंजी खाता								
	पूंजी खाता शेष	89,286	41,128	36,447	91,390	54,403	21,391	39,935
	i. विदेशी ऋण (निवल)	1,725	1,505	2,013	2,944	3,413	478	1,913
	ii. विदेशी वाणिज्यिक उधार (निवल)	1,570	-4,529	-6,102	-183	10,416	877	9,767
	iii. लघु आवधिक ऋण	-111	-1,610	6,467	13,900	2,021	1,298	1344
	iv. बैंकिंग पूंजी (निवल) जिसमें से:	11,618	10,630	-16,616	16,190	7,433	10,583	-5,702
	अनिवासी निक्षेप (निवल)	14,057	16,052	-12,367	9,676	10,387	6,838	5,034
	v. विदेशी निवेश (निवल) जिसमें से:	73,456	31,891	43,224	52,401	30,094	9,040	28,646
	A. प्रत्यक्ष विदेश निवेश (निवल)	31,251	36,021	35,612	30,286	30,712	16,983	21,327
	B. पोर्टफोलियो (निवल)	42,205	-4,130	7,612	22,115	-618	-7,943	7,319
	vi. अन्य अंतर्वाह (निवल)	1,028	3,242	7,460	6,138	1,026	-885	3967
III	भूलचूक	-1,021	-1,073	-480	902	-486	259	-211
IV	समग्र शेष	61,406	17,905	21,550	43,574	-3,339	-13,206	19,102
V	भण्डार परिवर्तन वृद्धि (-) / कमी (+)	-61,406	-17,905	-21,550	-43,574	3,339	13,206	-19,102

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: पी : प्राथमिक

मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पहले से ही प्रवर्तमान

क्र. सं.	करार का नाम	करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख	करार के कार्यान्वयन की तारीख और हाल की गतिविधियां
1	भारत-श्रीलंका एफटीए	28 दिसम्बर, 1998	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 मार्च, 2000 थी, सामानों के व्यापार, सेवाओं के व्यापार को शामिल करते हुए प्रस्तावित आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग करार (ईटीसीए), निवेश तथा आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए बातचीत प्रगति पर है। ग्यारह दौर की वार्ता पूरी कर ली गई है।
2	साफ्टा पर करार (भारत पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान)	4 जनवरी, 2004	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 जनवरी, 2006 थी (प्रशुल्क रियायतें 01 जुलाई, 2006 से कार्यान्वित की गई)
3	भारत-नेपाल व्यापार समझौता	27 अक्टूबर, 2009	समझौते की अवधि का विस्तार आगे और 7 वर्षों के लिए किया गया और यह वर्तमान में 26 अक्टूबर, 2023 तक लागू है। वर्ष 2018 में प्रारंभ, भारत नेपाल व्यापार समझौते की व्यापक समीक्षा जारी है।
4	भारत-भूटान व्यापार वाणिज्य और पारगमन करार	17 जनवरी, 1972	परस्पर सहमत संशोधनों के साथ, आवधिक रूप से पुनर्नवीकरण किया जाता है। 29 जुलाई, 2006 का करार 10 वर्षों तक वैध है। परस्पर सहमति से वैधता एक वर्ष की अवधि या प्रस्तावित नया करार प्रभावी होने की अवधि के लिए बढ़ाई जाती है। नवीकृत करार 12.11.2016 को किया गया और यह 29 जुलाई, 2017 से प्रभावी हुआ।
5	भारत-थाईलैंड एफटीए शीघ्र लाभ प्राप्ति योजना (ईएचएस)	9 अक्टूबर, 2003	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 सितंबर, 2004 थी।
6	भारत-सिंगापुर सीईसीए	29 जून, 2005	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 अगस्त, 2005 थी। भारत सिंगापुर सीईसीए की दूसरी समीक्षा संयुक्त रूप से पूरी की गई और भारत के प्रधानमंत्री के सिंगापुर दौरे के दौरान इसकी घोषणा 01 जून, 2018 को की गई।
7	भारत-आसियान सीईसीए-समान सेवाओं तथा निवेश व्यापार करार (ब्रुनेई, कम्बोडिया इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम)	13 th August, 2009 for goods and November, 2014 for Services and Investment	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत और मलेशिया, सिंगापुर थाईलैंड के संबंध में 01 जनवरी, 2010 को। ● भारत और वियतनाम के संबंध में 01 जून, 2010 को। ● भारत और म्यांमार के संबंध में 01 सितंबर, 2010 को। ● भारत और इंडोनेशिया के संबंध में 01 अक्टूबर, 2010 को। ● भारत और ब्रुनेई के संबंध में 01 नवंबर, 2010 को। ● भारत और लाओस के संबंध में 24 जनवरी, 2011 को। ● भारत और फिलीपींस के संबंध में 01 जून, 2011 को। ● भारत और कम्बोडिया के संबंध में 01 अगस्त, 2011 को। <p>सेवाएं और निवेश सेवाओं तथा निवेश हेतु समझौता कार्यान्वित होने की तारीख 01 जुलाई, 2015 थी।</p>
8	भारत दक्षिण कोरिया सीईपीए	7 अगस्त, 2009	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 जनवरी, 2010 थी। 2016 में दोनों ही पक्षों ने सीईपीए का और भी विस्तार करने की संस्तुति की थी। आठ दौर की वार्ता जून 2019 में पूरी कर ली गई है।
9	भारत जापान सीईपीए	16 फरवरी, 2011	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 अगस्त, 2011 थी।
10	भारत मलेशिया सीईसीए	18 फरवरी, 2011	समझौते के कार्यान्वयन की तारीख 01 जुलाई, 2011 थी।

स्रोत: वाणिज्य विभाग

पहले से ही प्रवृत्त तरजीही व्यापार करार (पीटीए)

क्रम सं.	करार का नाम	करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख	करार के कार्यान्वयन की तारीख और हालिया विकास
1	एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए) (बांग्ला देश, चीन, भारत कोरिया गणराज्य, लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य और श्रीलंका)	जुलाई, 1995 (2 नवंबर, 2005 को संशोधित)	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 1 नवंबर, 1976 थी।
2	व्यापार तरजीह है की वैश्विक प्रणाली (जीएसटी पी) (अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बेनिन, बोलीबिया, ब्राजील कैमरून, चिली, कोलम्बिया, क्यूबा, लोकतांत्रिक गणराज्य कोरिया, इक्वाडोर, मिस्र, धाना, गिनिया, गुयाना, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, मॉक्सिको, रक्को, मोजांबि, म्यांमार, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू, फिलापीन्स, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सुडान थाइलैण्ड, ट्रिनिडाड और टोबेगो, ट्यूनीशिया, तंजानिया, बेनेजुएला, वियतनाम, यूगोस्लाविया, जिम्बाबवे)	13 अप्रैल, 1988	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 19 अप्रैल, 1989 थी।
3	सार्क तरजीही व्यापार करार (एसएपीटीए) (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका)	11 अप्रैल, 1993	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 7 दिसम्बर, 1995 थी।
4	भारत-अफगानिस्तान	6 मार्च, 2003	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 13 मई, 2003 थी।
5	भारत-मेर्कोसुर (अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और युरुग्वे)	25 जनवरी, 2004	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 1 जून 2009 थी।
6	भारत-चिली	8 मार्च, 2006	संधि के कार्यान्वयन की तारीख 11 सितम्बर, 2007 थी। इस करार का 6 सितम्बर, 2016 को विस्तार कर दिया गया है और यह 16 मई, 2017 से लागू हुआ।

स्रोत: वाणिज्य विभाग

चालू व्यापार वार्ताएं

क्र. सं.	करार का नाम	स्थिति
1	भारत-यूरोपीय संघ बी टी आई ए	माल, सेवाओं, निवेश, स्वच्छता एवं फाइटोसेनिटरी उपायों, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, व्यापार सुविधा एवं सीमाशुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा आई पी आर एवं जी आई, इत्यादि के क्षेत्रों से संबंधित वार्ताएं, 28 जून 2007 को प्रारंभ हुईं। अब तक 16 दौर आयोजित हो चुके हैं।
2	भारत-श्रीलंका आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग करार (ई टी सी ए)	अब तक 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं।
3	भारत-थाईलैंड सी ई सी ए	83 मदों पर अर्ली हारवेस्ट स्कीम कार्यान्वित। अब तक भारत-थाईलैंड व्यापार वार्ता समिति (आई टी टी एन सी) की बैठकों के 30 दौर आयोजित हो चुके हैं।
4	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी करार (सी ई सी पी ए)	व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी करार के अन्तर्गत वस्तुओं, सेवा व्यापार, व्यापारिक उपचारों, एस पी एस/टी बी टी मुद्दों एवं विवाद समाधानों के बारे में वार्ताएं सी ई सी पी ए हेतु वार्ताओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
5	भारत-एफ्टा (ई एफ आी ए) टी ई पी ए (आइसलैण्ड, नार्वे, लिचेंस्टीन और स्विटजरलैण्ड)	भारत-ई एफ वी ए टी ई पी ए (व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी करार) जनवरी, 2008 में प्रारंभ किया गया। अब तक 17 दौर की वार्ताएं आयोजित हो चुकी हैं।
6	भारत-न्यूजीलैंड एफ टी ए/सी ई सी ए	अब तक सी ई सी ए की 10 दौर की वार्ताएं आयोजित हो चुकी हैं। 10वें दौर की आयोजन 17-18 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में किया गया।
7	भारत-इजराइल व्यापार करार	अब तक भारत-इजराइल एफ टी ए पर 9 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं।
8	भारत-सिंगापुर सी ई सी ए (तृतीय समीक्षा)	भारत-सिंगापुर सी ई सी ए की तृतीय समीक्षा 01 सितंबर 2018 को प्रारंभ हुई।
9	भारत-एस ए जी यू पी टी ए (दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वाजीलैण्ड और (नाबिया)	अब तक 5 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं
10	भारत-मर्कोसुर पी टी ए विस्तार (अर्जेटीना, ब्राजील, परागुवे और उग्रवे)	मौजूदा भारत-मर्कोसुर पी टी ए का विस्तार किया जा रहा है। संयुक्त प्रशासनिक समिति (जे ए सी) की तृतीय बैठक 29 सितंबर, 2016 को ब्राजीलिया में आयोजित की गई। 14 सितंबर 2017 को दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
11	बिम्स्टेक, सी ई सी ए (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल)	अब तक व्यापार वार्ता समिति (टी एन सी) की 21 बैठकें हो चुकी हैं। बिम्स्टेक व्यापार वार्ता समिति की 21वीं बैठक का आयोजन 18-19 नवंबर, 2018 के दौरान ढाका, बांग्लादेश में किया गया था।

On-going Trade Negotiations

क्र. सं.	करार का नाम	स्थिति
12	भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (जी सी सी) फ्रेमवर्क करार	अब तक वर्ष 2006 तथा 2008 में दो दौर की वार्ता हो चुकी है। वर्ष 2011 में जी सी सी सचिवालय को सभी देशों के साथ तब तक वार्ता स्थगित रखने के लिए कहा गया, जब तक कि जी सी सी राज्यों द्वारा वार्ता के मुद्दों की पूरी तरह से समीक्षा नहीं कर ली जाती। हाल ही में जी सी सी सचिवालय ने दिनांक 6 नवंबर, 2019 के अपने मौखिक नोट के माध्यम से सूचित किया है कि जी सी सी, भारत-जी सी सी एफ टी ए वार्ता को फिर से शुरू करने का स्वागत करती है।
13	भारत-कनाडा एफ टी ए	अब तक भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक नीति समझौता (सी ई पीए) के बीच दस दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का दसवें दौर नई दिल्ली में अगस्त, 2017 में हुआ था। इसका एक अंतर-समीप दौर ओटावा में फरवरी, 2018 में आयोजित किया गया था।
14	भारत-ऑस्ट्रेलिया	नौ दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का नवां दौर नई दिल्ली, भारत में 21-23 सितंबर, 2015 को संपन्न हुआ।
15	भारत-मलेशिया सी ई सी ए (प्रथम समीक्षा)	भारत-मलेशिया सी ई सी ए के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु भारत-मलेशिया संयुक्त समिति की पहली बैठक का आयोजन 8, दिसंबर 2014 को किया गया।
16	भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता (प्रथम समीक्षा)	भारत ने भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता (ए आई आर जी ए) की समीक्षा के लिए अनुरोध किया है।
17	भारत-कोरिया सी ई पी ए समीक्षा	भारत-कोरिया सी ई पी ए को अपग्रेड करने के लिए अब तक संधि वार्ताओं के 8 दौर आयोजित किए गए हैं। 8वां दौर 17-18 जून 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
18	भारत-ईरान पी टी ए	अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं
19	भारत-पेरू पी टी ए	अब तक 4 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं
20	भारत-ई ए ई यू तकनीकी परामर्श	तकनीकी परामर्श का पहला दौर 30-31 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।
21	भारत-बंगलादेश सी ई पी ए	सी ई पी ए की सुगमता की जांच करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन किया जा रहा है। भारत ने यह अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय व्यापार केंद्र की पहचान की ली है और बंगलादेश से इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त संगठन की पहचान करने का अनुरोध किया गया है।
22	भारत-चिली पी टी ए (द्वितीय विस्तार)	भारत-चिली के दूसरे प्रसार की पहली बैठक 10-11 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

स्रोत: वाणिज्य विभाग

अनुबंध 2 (जारी)

विदेशी मुद्रा रिजर्व में परिवर्तनों का सार

(यू एस डालर बिलियन)

क्रम सं.	वर्ष	वित्त वर्ष की समाप्ति (मार्च समाप्ति) पर विदेशी मुद्रा रिजर्व	रिजर्व में कुल वृद्धि (+) / (-)	रिजर्व में बी ओ पी आधार वृद्धि (+) / कमी (-)	मूल्यांकन प्रभाव के कारण (रिजर्व में) लाभ (+) / हानि (-)
1	2007-08	309.7	110.5	92.2	18.4
2	2008-09	252.0	-57.7	-20.1	-37.7
3	2009-10	279.1	27.1	13.4	13.6
4	2010-11	304.8	25.8	13.1	12.7
5	2011-12	294.4	-10.4	-12.8	2.4
6	2012-13	292.0	-2.4	3.8	-6.2
7	2013-14	304.2	12.2	15.5	-3.3
8	2014-15	341.6	37.4	61.4	-24.0
9	2015-16	360.2	18.5	17.9	0.6
10	2016-17	370.0	9.8	21.6	-11.8
11	2017-18	424.5	54.6	43.6	11.0
12	2018-19	412.9	-11.7	-3.3	-8.3
13	H1: 2018-19	400.5	-24.0	-13.2	-10.8
14	H1: 2019-20	433.7	20.8	19.1	1.7

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई)